दैनिक लद्दाख टुडे

वर्षः 01 अंकः 26 । लद्दाख, गुरूवार 15 अक्टूबर 2026 । पृष्ठः 8 मूल्य 2 रुपए । RNI NO.: LAHIN/26/A7900

कैबिनेट ने सोशल असिस्टेंस स्कीम के लिए 53,428 करोड़ रुपये किए मंजूर

विकलांगता पेंशन के नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को श्नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्रामश (एनएसएपी) को 2026–27 से 2030–31 तक पांच साल के लिए जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। इसमें विकलांगता पेंशन पाने वालों के लिए पात्रता के नियमों और सहायता की दरों में बदलाव किया गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस स्कीम का नाम बदलकर श्प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजनाश कर दिया जाएगा, और इसके पेंशन और परिवार लाभ वाले हिस्सों के नाम भी बदल दिए जाएंगे। बदले हुए नियमों के तहत, विकलांगता पेंशन स्कीम में 79 साल तक की उम्र के लोगों को हर महीने 375 रुपये और 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 625 रुपये की सहायता मिलेगी।

पेंशन पाने के लिए विकलांगता का पैमाना 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। कम से कम उम्र की शर्त भी हटा दी गई है, जिससे विकलांग लोग जन्म से ही सहायता पाने के हकदार हो जाएंगे। बयान में कहा गया है कि विकलांगता पेंशन स्कीम के तहत पात्रता के नए नियम, लाभार्थियों का दायरा और सहायता की दरें गाइडलाइंस

जारी होने के तीन महीने के भीतर लागू कर दी जाएंगी।

बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन स्कीम और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम अपने मौजूदा रूप में जारी रहेंगी। कैबिनेट की इस मंजूरी से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया जाएगा, जबकि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम को प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना कहा जाएगा।

इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया जाएगा, और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना हो जाएगा। 15 अगस्त

■ शेष पेज 2...

हेल्थकेयर में मानवीय संवेदना को प्राथमिकता दें: एलजी मनोज सिन्हा

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को एडवांसिंग इंटरनल मेडिसिन–फ्रॉम एविडेंस टू एक्सीलेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस (इंटरनल मेडिसिन में प्रगति–क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबूत से उत्कृष्टता तक) विषय पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए बधाई दी। अपने संदेश में, उपराज्यपाल ने संपूर्ण और मरीज़–केंद्रित हेल्थकेयर प्रदान करने में इंटरनल मेडिसिन की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।

उपराज्यपाल ने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर साधारण दिखने वाले लक्षणों से जटिल स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान

करने के चुनौतीपूर्ण काम का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इंटरनल मेडिसिन की ताकत मानव शरीर को एक आपस में जुड़े हुए सिस्टम के रूप में देखने और क्लिनिकल ज्ञान, अनुभव और सावधानीपूर्वक अवलोकन के माध्यम से मरीज़ की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को समझने की क्षमता में निहित है।

उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि अवलोकन, तर्क, मानवीय समझ और साहस एक डॉक्टर

■ शेष पेज 2...

लद्दाख में रणनीतिक कनेक्टिविटी होगी मजबूत, पीएम मोदी करेंगे 3350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वे 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में

लगभग 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्हें देश को समर्पित करेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और निम्मू–पदुम–दारचा रोड शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी और रणनीतिक आवाजाही को मज़बूत करेंगे। मोदी ने एक्स पर लिखा कि कल, 15 अक्टूबर को, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और उन्हें देश को समर्पित करूंगा। इनमें शामिल हैंरू लेह में कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग; निम्मू–पदुम–दारचा रोड, जो कनेक्टिविटी और रणनीतिक आवाजाही को बेहतर बनाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में 9 मेगावाट का हनु हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

■ शेष पेज 2...

संक्षिप्त...

कश्मीर क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में तीन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू–कश्मीर क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग (एससीडब्ल्यू) ने बुधवार को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में तीन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

उन्होंने बताया कि एससीडब्ल्यू कश्मीर ने रणबीर दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दर्ज मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ श्रीनगर की एंटी–करप्शन स्पेशल जज की अदालत में चार्जशीट पेश की।

आरोपियों की पहचान बीरवाह सब–डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिस में हेल्पर अब्दुल रशीद गोजरी; बडगाम के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर

■ शेष पेज 2...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एसआईआर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 28 अक्टूबर तक आगे बढ़ाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 28 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सूची और हर नोटिस के लिए खास वजहों को सार्वजनिक करे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मामला उठाया। भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक अर्जी दाखिल की है जिसमें चुनाव आयोग से उन मतदाताओं को शामिल करने के लिए सही तरीका अपनाने का

■ शेष पेज 2...

सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने आदेश दिया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की एक कॉपी 14वें आरोपी, शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के वकील को दी जाए और मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की।

एजेंसी का आरोप है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला सूर्यवंशी, जिसे 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, सह–आरोपी शुभम खैरनार का करीबी सहयोगी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक, सूर्यवंशी ने खैरनार के साथ मिलकर कई उम्मीदवारों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर

■ शेष पेज 2...

---- जम्मू ----

अधिकतम – $42^{0}C$

न्यूनतम – $32^{0}C$

---- श्रीनगर ----

अधिकतम – $36^{0}C$

न्यूनतम – $24^{0}C$

कश्मीर में बीजेपी को वैचारिक बढ़त मिल रही है: सतीश पूनिया

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। बीजेपी ने बुधवार को कहा कि कश्मीर में उसके लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल बन रहा है क्योंकि उसे वैचारिक मोर्चे पर अच्छी बढ़त मिल रही है। साथ ही, पार्टी ने जम्मू–कश्मीर में अगले चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का भरोसा जताया।

जम्मू–कश्मीर का प्रभारी बनाए जाने के बाद जम्मू में पार्टी नेतृत्व की बैठक की अध्यक्षता करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अपना संगठनात्मक आधार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, आज कश्मीर वही जगह है जहां लाखों लोग बहुत सम्मान और गरिमा के साथ तिरंगा फहराते हैं। कश्मीर के लोगों ने वैचारिक रूप से बीजेपी को अपना लिया है। जम्मू–कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर

टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का कामकाज लोगों के सामने है।

उन्होंने कहा, जहां तक उमर अब्दुल्ला सरकार की बात है, तो उनके काम करने का तरीका कश्मीर के लोगों के सामने है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बीजेपी यहां पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और लोग पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे। पूनिया ने जम्मू–कश्मीर में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं सहित विकास कार्यों

■ शेष पेज 2...

भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर मतभेद सुलझा रहे हैं, अंतिम समझौते के करीब: जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील पर मतभेद दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और बातचीत एक अंतिम समझौते (लैंडिंग पॉइंट) की ओर बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच रणनी. तिक साझेदारी के मूल आधार में

कोई बदलाव नहीं आया है।

ट्रेड बातचीत पर विदेश मंत्री की यह टिप्पणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के एक हफ्ते से ज़्यादा समय बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेड डील पर बातचीत एक ष्ठहरावष (प्लेटो) की स्थिति में पहुँच गई है।

मंगलवार शाम ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में दोनों पक्षों के बीच बातचीत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक रूप से इसके बारे में

■ शेष पेज 2...

एलजी सिन्हा ने हिमालय को बचाने को ज़रूरी बताया

पहाड़ों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दिया ज़ोर

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर के उप–राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को हिमालय में इकोलॉजिकल बैलेंस (पारिस्थितिक संतुलन) बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह इलाका न सिर्फ़ नदियों का स्रोत है, बल्कि बायोडायवर्सिटी (जैव विविधता) का रक्षक और जलवायु को नियंत्रित करने वाला एक अहम हिस्सा भी है।

सिन्हा ने श्रीनगर में शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ़ कश्मीर

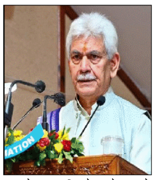

(एसकेयूएएसटी–के) में 13वें सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट

■ शेष पेज 2...

मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस: सौरभ राजपूत की हत्या के लिए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सज़ा

मेरठ। बुधवार को मेरठ की एक अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल को मौत की सज़ा सुनाई। इस मामले को श्ब्लू ड्रम मर्डर केसश के नाम से जाना जाता है।

वकील कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा, अदालत ने धारा 302 के तहत 50,000 रुपये और धारा 238ए के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। पूरा देश इस पर नज़र रखे हुए था; जनता की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को क्या सज़ा मिलेगी। वे सदमे की हालत में लग रहे थे; वे हैरान थे। मौत की सज़ा का सामना कर रहे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बचाव पक्ष ने कई तर्क दिए थे–

■ शेष पेज 2...

कश्मीर के उच्च इलाकों में रात भर ताज़ा बर्फ़बारी हुई

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह कश्मीर के उच्च इलाकों में कई जगह बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई, क्योंकि एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण रात भर ताज़ा बर्फ़बारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि मैदानी इलाकों में रात भर बारिश हुई।

■ शेष पेज 2...

जेएंडके हाई कोर्ट ने आज़ाद और रैना को सरकारी घर अपने पास रखने की इजाज़त देने वाली पॉलिसी पर साफ़ जानकारी मांगी

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं के लिए सरकारी आवास से जुड़ी पॉलिसी पर साफ़ जानकारी मांगी है। कोर्ट को बताया गया कि एक कमेटी की सिफ़ारिशों के बाद, जेके के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविंदर रैना अगले साल मार्च तक अपने सरकारी आवास में रह सकते हैं।

प्रोफ़ेसर एस.के. भल्ला की तरफ़ से 12 अक्टूबर को दायर एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए, चीफ़ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस राजेश सेखरी की डिवीज़न बेंच ने प्रशासन से उस पॉलिसी के बारे में सवाल किया जिसके तहत इन दो राजनीतिक नेताओं को सरकारी आवास में बने रहने की इजाज़त दी गई है।

यूटी प्रशासन की तरफ़ से पेश हुई सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका को. हली ने कोर्ट को बताया कि एक तय कमेटी ने 14 अगस्त को हुई बैठक में आज़ाद और जेके बीज. ेपी के पूर्व अध्यक्ष रैना के मामलों पर विचार किया था। कोहली ने बताया कि कमेटी ने दोनों नेताओं के पक्ष में आवास आवंटन जारी रखने की सिफ़ारिश की थी।

कोहली ने बेंच को बताया कि इसके बाद सिफ़ारिशें सक्षम अधिकारी के सामने रखी गईं, जिन्होंने उचित विचार–विमर्श के बाद उन्हें मार्च 2027 तक या अगले रिव्यू तक, जो भी पहले हो, आवासीय आवास अपने पास रखने की इजाज़त दे दी।

■ शेष पेज 2...

ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना होगा: डिप्टी सीएम चौधरी

शिव टाइम्स संवाददाता

गांदरबल। जम्मू–कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश को एक पारदर्शी, सक्रिय और निष्पक्ष चुनाव आयोग की ज़रूरत है। चुनाव

■ शेष पेज 2...

कैबिनेट ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह कुल 2009.61 करोड़ रुपये का भुगतान है, जो उनके बेहतरीन काम के लिए दिया जा रहा है।

योग्य रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। सरकार ने कहा, इस साल भी, लगभग 11.40 लाख नॉन–गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी के बराबर पीएलबी की रकम दी जा रही है। पीएलबी का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के कामकाज में सुधार के लिए प्रेरित करने का काम करता है।

सरकार ने आगे कहा, हर योग्य रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह रकम रेलवे के अलग–अलग कैटेगरी के

■ शेष पेज 2...

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

कश्मीर क्राइम ब्रांच ने...

के ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर मंजूर अहमद वानी; और रिटायर्ड सब-डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर (एसडीएओ) पीर अब्दुल रशीद के तौर पर की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 15 फरवरी 2022 को सेंट्रल कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिली एक सूचना से शुरू हुआ था, जिसमें कुछ अधिकारियों द्वारा गलत फायदे पाने के लिए सर्विस रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। जांच-पड़ताल के दौरान पता चला कि गोजरी ने कथित तौर पर जन्म तिथि का एक जाली सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसमें उसकी जन्म तिथि 1975 (असली वर्ष) के बजाय 27 फरवरी 1973 दिखाई गई थी।

इसके बाद, पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब पुलिस स्टेशन एससीडब्ल्यू कश्मीर) में मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डेली वेजर (दिहाड़ी मजदूर) के तौर पर शुरुआती नियुक्ति के समय आरोपी की उम्र 17 साल 2 महीने थी। उन्होंने बताया कि बाकी दो आरोपियों ने कथित तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए उसके सर्विस रिकॉर्ड में गलत जन्म तिथि दर्ज करने में मदद की, जिससे उसकी सर्विस को रेगुलर करने में आसानी हुई।

जांच के दौरान, एफआईआर के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हुए। उन्होंने आगे बताया कि नौकरी कर रहे दो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मंजूरी और अनुमति मिलने के बाद, श्रीनगर की एंटी-करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज के सामने चार्जशीट पेश कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली...

निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके नाम दिल्ली में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। इसमें उनसे यह घोषणा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वे पहली बार शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया था और इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होने की संभावना है। उन्होंने बेंच से अनुरोध किया कि याचिका पर 30 अक्टूबर से पहले सुनवाई की जाए।

बेंच ने मामले की सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर कर दी। जब भूषण ने उससे पहले सुनवाई का आग्रह किया, तो बेंच ने कहा, हम एक ऐसा आदेश पारित करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस मामले को देख लेगा। 26 सितंबर को, चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रहे एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी थी, और अब अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जानी है।

सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ था, जिसमें श्लॉजिकल विसंगतियोंश की श्रेणी में मतदाताओं के वर्गीकरण से जुड़े मानदंडों, परिभाषाओं, एल्गोरिदम पैरामीटर और ऑपरेशनल गाइडलाइंस का खुलासा करने की भी मांग की गई थी। हाल ही में, याचिकाकर्ताओं ने लंबित याचिका में एक अर्जी दाखिल की है। इस अर्ज़ी में मांग की गई है कि पहले से रजिस्टर्ड किसी भी वोटर को शफॉर्म 6श में दिया गया वह डिक्लेरेशन (घोषणा-पत्र) जमा करने के लिए न कहा जाए, जो असल में उस वोटर पर लागू नहीं होता है। साथ ही, यह भी मांग की गई है कि पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स को शामिल करने के लिए कोई सही फॉर्म या डिक्लेरेशन तय किया जाए।

सीबीआई ने नीट पेपर...

उपलब्ध कराया और उनके परिवारों से पैसे लिए।

सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि सूर्यवंशी ने कथित तौर पर उम्मीदवारों को नांदेड़ में एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा, जहां उन्हें पेपर दिया गया। उसने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट और पहचान पत्र अपने पास रख लिए ताकि यह पक्का हो सके कि वे परीक्षा के बाद पेमेंट कर दें।

12 अगस्त को, पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट का संज्ञान लिया।

पिछली चार्जशीट के मुताबिक, एजेंसी ने 13 मई को राजस्थान में मांगीलाल, दिनेश और विकास बिवाल की गिरफ्तारी के साथ कार्रवाई शुरू की थी। उनके मोबाइल फोन में 29 अप्रैल को टेलीग्राम के जरिए मिली लीक हुई पीडीएफ फाइलें थीं। उसी दिन, एजेंसी ने गुरुग्राम में यश यादव और नासिक में शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया। 13 मई को एक और अहम गिरफ्तारी पुणे में धनंजय लोखंडे की हुई। पकड़े जाने से पहले उसने सबूत मिटाने के लिए कथित तौर पर अपना फोन नष्ट करने की कोशिश की थी।

अगले दिन पुणे में मनीषा संजय वाघमारे को गिरफ्तार किया गया। पहले दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, वाघमारे पैसे के बदले नीट-यूजी 2026 के सवाल लीक करने और उन्हें फैलाने की साजिश रचने वालों में से एक मुख्य व्यक्ति था और उसने उम्मीदवारों और विषय विशेषज्ञों के बीच कड़ी का काम किया।

पूछताछ के बाद, एजेंसी ने 15 मई को लातूर से कथित मास्टरमाइंड पी.वी. कुलकर्णी को और उसके बाद 16 मई को पुणे से मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया। लातूर में एक कोचिंग सेंटर के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर को 17 मई को हिरासत में लिया गया। इस मामले में आखिरी गिरफ्तारियां 22 मई को लातूर से मनीषा संजय हवलदार की, और 26 मई को पुणे से तेजस शाह और लातूर से डॉ. मनोज शिरुरे की हुईं।

हेल्थकेयर में मानवीय...

के मुख्य गुण हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉक्टर अक्सर परिवारों के लिए चिकित्सा संपर्क का पहला बिंदु होते हैं और कई मामलों में, विश्वास, करुणा और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित पीढ़ियों तक चलने वाले संबंध बनाते हैं।

उपराज्यपाल ने अपने संदेश में मेडिकल शिक्षा और हेल्थकेयर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर की सराहना की और कहा कि इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित डॉक्टरों की पीढ़ियां जम्मू-कश्मीर और देश भर में सेवा करना जारी रखे हुए हैं। उपराज्यपाल ने उभरती हुई हेल्थकेयर चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, हालांकि संक्रामक रोग चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, फैटी लिवर रोग और हृदय संबंधी बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों और मरीज़ों तक उतनी ही प्रभावी ढंग से पहुंचे जितनी शहरी केंद्रों में पहुंचती है।

उपराज्यपाल ने मेडिकल बिरादरी से स्वदेशी अनुसंधान को मजबूत करने और भारत की विविध आबादी के लिए प्रासंगिक सबूत तैयार करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की जनसांख्यिकीय विविधता, डॉक्टरों की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ मिलकर, वैज्ञानिक खोज और नवाचार के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा, "मेडिकल साइंस में ऐतिहासिक तरक्की हो रही है और नई दवाओं व जांच के तरीकों ने इलाज के लिए नई संभावनाएं पैदा की हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह पक्का करना है कि ये नई तकनीकें और तरीके सिर्फ़ बड़े शहरों के डॉक्टरों तक ही सीमित न रहें, बल्कि गांवों के डॉक्टरों तक भी पहुंचें। हमें यह पक्का करना होगा कि सुविधाओं और उपलब्ध साधनों के मामले में शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच ज़रा भी फ़र्क न हो। इस कॉन्फ्रेंस का पहला मकसद यही होना चाहिए।"

लद्दाख में रणनीतिक...

और पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेह में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क, और प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 जल निकाय भी शामिल हैं।

उन्होंने आगे लिखा 9 मेगावाट का हनु हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर; लेह में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क; प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 जल निकाय। मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, लद्दाख की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेंगे और वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। उन्होंने कहा, ष्ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, समृद्ध विरासत को संरक्षित करेंगे और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दोपहर करीब 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ के पांच बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और उन्हें देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये पांच प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेंगे और क्षेत्र में जल सुरक्षा को बढ़ाएंगे।

प्रधानमंत्री लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर 640 करोड़ की लागत से बनी नई पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 23,800 वर्ग मीटर में फैले इस आधुनिक टर्मिनल को हर साल 35 लाख यात्रियों की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, यह सुविधा लद्दाख के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को दिखाती है। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के मेल से बना यह टर्मिनल यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाएगा और देश के बाकी हिस्सों के साथ हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा बनाई गई 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क को देश को समर्पित करेंगे। दूर-दराज़ ज़ंस्कार घाटी से होते हुए लेह में निम्मू को हिमाचल प्रदेश में दारचा से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर देती है, जो श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह हाईवे के साथ-साथ काम करेगी। ऊँचाई पर स्थित शिंकुन ला पास समेत हिमालय के मुश्किल रास्तों से गुज़रने वाली यह सड़क इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी रणनीतिक अहमियत सेना के लिए ऑपरेशनल मोबिलिटी बढ़ाने और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को मजबूत करने में है। इससे ज़ंस्कार के लोगों को भी हेल्थकेयर, शिक्षा, बाज़ार और ज़रूरी सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिलेगी।

कैबिनेट ने सोशल...

1995 को शुरू की गई एनएसएपी योजना, संविधान के राज्य के नीति-निर्देशकों के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र की ज़िम्मेदारी के तौर पर गरीब परिवारों को मदद देती है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 100 प्रतिशत मदद देती है ताकि देश भर में सभी लाभार्थियों को एक जैसी सहायता मिल सके।

विकलांगता पेंशन पाने वालों के लिए पात्रता के नए नियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार हैं। इस कानून में 40 प्रतिशत विकलांगता को बेंचमार्क माना गया है और यह प्रावधान है कि विकलांगता से जुड़ी सहायता राशि, दूसरी श्रेणियों की समान योजनाओं की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए।

एलजी सिन्हा ने...

समिट के समापन सत्र में अपने संदेश में कहा, हिमालय के इकोलॉजिकल बैलेंस में किसी भी तरह की गड़बड़ी के दूरगामी परिणाम होंगे।

उन्होंने हिमालय के इकोसिस्टम को बचाने की अहमियत पर ज़ोर दिया और पहाड़ों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विज्ञान पर आधारित और लोगों पर केंद्रित नज़रिए की वकालत की।

मेरठ ब्लू ड्रम...

जैसे कि हत्या को किसी ने नहीं देखा और दोनों आरोपियों की बेटियाँ हैंकुलेकिन इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत इतने मज़बूत, अहम और सटीक थे कि उनसे उनका अपराध साबित हो गया।

आगे विस्तार से बताते हुए दुबे ने कहा कि इसका मुख्य आधार हत्या का तरीका ही था। उन्होंने कहा, उसने अपने पति जिससे उसने प्यार करके शादी की थी की हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके तीन टुकड़े कर दिए और अवशेषों को एक नीले ड्रम में छिपा दिया। यह बहुत सोच-समझकर रची गई साज़िश और रणनीति थी। उसने शांत और स्थिर दिमाग से हत्या को अंजाम दिया। इसलिए, ऐसी पहले से योजना बनाकर की गई हत्या के लिए मौत की सज़ा ही उचित सज़ा थी।

वकील ने इसे देश के अदालती फ़ैसलों में एक अहम फ़ैसला बताया। उन्होंने कहा, किसी महिला को मौत की सज़ा सुनाया जाना अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली घटना है। उसकी बेटी के बारे में बात करें तो वह छह साल तक अपनी माँ के साथ रह सकती है।

अदालत ने पहले इस मामले की सुनवाई की थी, जिसमें मुस्कान पर साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साज़िश रचने और उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने 22 गवाह पेश किए गए। मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस मर्चेंट नेवी के 29 साल के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है, जिसमें उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके स्कूल के साथी व पार्टनर साहिल शुक्ला आरोपी हैं।

कश्मीर के उच्च...

उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश का अनुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से ऊंचे इलाकों में कई जगहों पर रात भर हल्की से मध्यम बर्फ़बारी हुई। जहां कश्मीर के उच्च इलाकों में कई जगहों पर ताज़ा बर्फ़बारी हुई, वहीं कई अन्य जगहों पर यह दूसरे दिन भी जारी रही।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में पहलगाम टूरिस्ट रिज़ॉर्ट और उसके आस-पास के इलाकों में रात भर बर्फ़बारी हुई। गुलमर्ग और सोनमर्ग टूरिस्ट रिज़ॉर्ट के साथ-साथ ज़ोजिला एक्सिस, राज़दान टॉप और उत्तरी कश्मीर के गुरेज़ में तुलेल में भी रुक-रुक कर बर्फ़बारी होती रही।

घाटी के मैदानी इलाकों, जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर भी शामिल है, में रात भर बारिश हुई, लेकिन सुबह बादल छंटने के बाद धूप निकल आई। मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फ़बारी की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर गरज-चमक, तेज़ हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है।

विभाग ने कहा कि 16 अक्टूबर को मौसम आम तौर पर शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद, 24 अक्टूबर तक मौसम आम तौर पर शुष्क रहेगा।

जेएंडके हाई कोर्ट ने...

हालांकि, बेंच ने ऐसे आवंटन से जुड़ी पॉलिसी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और कोहली से उन नियमों के बारे में पूछा जिनके तहत तय कमेटी राजनीतिक नेताओं को सरकारी आवास अपने पास रखने की इजाज़त देने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है।

बेंच ने पूछा, इस कोर्ट ने ऐसी दलीलों पर वरिष्ठ एएजी से सवाल किया है कि जम्मू-कश्मीर यूटी में सरकारी आवास अपने पास रखने से जुड़ी पॉलिसी क्या है... और तय कमेटी को यह विचार करने की शक्ति कहाँ से मिलती है कि क्या राजनीतिक व्यक्तियों के पास ऐसा सरकारी आवास रहना चाहिए।

कोहली ने उचित हलफ़नामा दायर करने और राजनीतिक व्यक्तियों के सरकारी आवास अपने पास रखने के लिए लागू एक समान पॉलिसी के मुद्दे पर कोर्ट की मदद करने के लिए समय मांगा। उनकी अपील को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर के लिए तय कर दी।

सुनवाई के दौरान, जो वर्चुअली हुई क्योंकि बेंच अभी श्रीनगर में है, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सुरक्षा के आधार पर सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्ज़े को सही नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील, सीनियर एडवोकेट एस एस अहमद और सुप्रिया चौहान ने 26 दिसंबर, 2022 के एक आदेश का ज़िक्र किया। इस आदेश में एक डिवीज़न बेंच ने सुरक्षा कारणों से सरकारी संपत्तियों से बेदखली के ख़िलाफ़ कुछ लोगों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया।

भल्ला द्वारा 2020 में दायर की गई इस पीआईएल के कारण, 2018 में विधानसभा भंग होने और उसके बाद हाई कोर्ट के दखल के बाद 180 से ज़्यादा नेताओं को सरकारी आवासों से बेदखल किया गया था।

ज्ञानेश कुमार को...

आयोग के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए, चौधरी ने गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर के दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा कि युवाओं की चिंताओं को दबाने के बजाय उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, अगर युवाओं और लोगों को लगता है कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। युवा सड़कों पर हैं और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना ही होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, जबकि उनके माता-पिता ने उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए बहुत त्याग किया है। उन्होंने कहा, आज भारत के युवा रोज़गार की मांग कर रहे हैं। उनके माता-पिता ने उन्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पा रही है। वोट चोरी के आरोपों का ज़िक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि युवा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगाया कि उनकी चिंताओं का जवाब बल प्रयोग से दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा, वे कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं और उनके वोट भी चोरी हो रहे हैं। उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह कैसा न्याय है?

उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों समेत युवा प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ बल प्रयोग की भी निंदा की और कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। उन्होंने कहा, ये युवा हमारे देश का भविष्य हैं। आप बल प्रयोग करके उन्हें चुप नहीं करा सकते। यह दमन है और ऐसा दमन जारी नहीं रह सकता। चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग ज़रूरी है।

कैबिनेट ने 11 लाख...

कर्मचारियों को दी जाएगी, जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ़ और दूसरे ग्रुप शसीश स्टाफ़। सरकार ने कहा, साल 2025-26 में रेलवे का कामकाज बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1670 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब यात्रियों को यात्रा कराई।

कश्मीर में बीजेपी...

का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी पूरे जम्मू-कश्मीर में अपना संगठनात्मक आधार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, आज कश्मीर में पुल बन रहे हैं, जिनमें चिनाब पुल भी शामिल है। लोगों को आयुष्मान भारत और आवास से लेकर उज्ज्वला और कई अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह वही कश्मीर है जहां अब लाल चौक पर सम्मान और गरिमा के साथ तिरंगा फहराया जाता है।

पूनिया ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके नकारात्मक बयान पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनकी हताशा को दर्शाते हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा, पिछले 12 सालों में मोदी जी ने सामाजिक और व्यवहार से जुड़े बदलाव लाने के लिए जो काम किया है, उनका विज़न सिर्फ़ एक नारा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ने देश की तरक्की, विकास और आत्म-सम्मान में बड़ा योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विज़न ने अलग-अलग इलाकों के लोगों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को मज़बूत किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस को लोगों ने उसकी नीतियों और कामकाज के तरीके की वजह से नकार दिया है। जम्मू-कश्मीर में अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बात करते हुए पुनिया ने कहा कि वह पार्टी संगठन को मज़बूत करने और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर काम करेंगे।

भारत और अमेरिका...

खुलकर बात करने में सहज नहीं हूँ। जयशंकर ने कहा कि भारत के व्यापार मंत्री, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) और संबंधित अन्य अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

जब देश अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था के साथ बातचीत करते हैं, तो ज़ाहिर है कि इसका एक हिस्सा वह होता है जो आप खुद और अमेरिका के बीच तय करते हैं, और दूसरा हिस्सा यह होता है कि आप प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कैसा प्रदर्शन करते हैं। और यह हिस्सा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि हर किसी ने डील तय नहीं की है। मुझे लगता है कि लोग, वहाँ के व्यापार मंत्री, यूएसटीआर (अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि) और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वे इसे सुलझा रहे हैं।

जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि यह मामला अब किसी नतीजे की ओर बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका 2025 की शुरुआत से ही एक प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इसका मकसद टैरिफ से जुड़े विवादों को सुलझाना, गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करना और दोनों देशों के बीच बाज़ार तक पहुँच को बढ़ाना है। भारत अमेरिकी बाज़ार में अपने सामान के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर टैरिफ दरें चाहता है।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा था कि अमेरिका और भारत एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं, लेकिन समझौता तुरंत होने की उम्मीद नहीं है।

ग्रीर ने कहा कि दोनों पक्षों ने उन मुद्दों की पहचान कर ली है जो अभी तक सुलझे नहीं हैं और वे समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। अपनी बात रखते हुए, जयशंकर ने आर्थिक जुड़ाव को लेकर वाशिंगटन के नए नज़रिए पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, टैरिफ के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका का नज़रिया बुनियादी तौर पर अलग है। लेकिन यह भी किसी और चीज़ का संकेत है। आज अमेरिका फिर से औद्योगिकरण करने और अपनी अर्थव्यवस्था तक पहुँच की शर्तों को नए सिरे से तय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

HELP LINE

IMPORTANT CONTACT NUMBERS – UT LADAKH

POLICE DEPARTMENT (SPs)

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	EMAIL
1	SP Leh	Shree Raam R (IPS)	8899222100	01982-244031	ssp-leh1@police.ladakh.gov.in
2	SP Nubra	Sh. Stanzin Losal (JKPS)	9419037139 8825045363	–	spnubra@gmail.com (Temporary)
3	SP Changthang	Sh. Syed Zaheer Abass (JKPS)	9797995888	7006368375	sp-changthang@police.ladakh.gov.in
4	SP Sham	Sh. Aijaz Malik (JKPS)	9419923000	6006424325	sp-sham@police.ladakh.gov.in
5	SP Kargil	Sh. Niten Yadav (IPS)	9999339994	01985-232645/232704	sspkargil@police.ladakh.gov.in Fax No. 232645
6	SP Drass	Sh. Istiqaq A. Kacho (JKPS)	8492097235	–	sp-drass@police.ladakh.gov.in
7	SP Zanskar	Sh. Rigzen Sangdup	9419287779 6006164711	–	sp-zanskar@police.ladakh.gov.in

DEPUTY COMMISSIONERS

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	PA TO DC / EMAIL
1	DC Leh	Sh. Romil Singh Donk (IAS)	7982319218	01982-252685	Stanzin – 8494072166
2	DC Kargil	Sh. Rakesh Kumar (IAS)	8604286353	01985-232216	Skarma Gurmat – 9622254259
3	DC Changthang	Sh. Nitish Rajora (IAS)	7053991969	(Temporary)	PA to DC – Kunzes Dolma 6005297553
4	DC Nubra	Sh. Mukul Beniwal (IAS)	8800308665	01982-252049	–
5	DC Zanskar	Sh. Omkar Rajendra Gundage (IAS)	8668894331	–	dc-zanskar@ladakh.gov.in
6	DC Sham	Smt. Kunzes Angmo	9419179108	–	–
7	DC Drass	Sh. Imteeaz Kacho (JKAS)	–	–	–

These numbers are for public assistance and urgent communication only.
FOR ANY EMERGENCY, DIAL 112

Created by Universal Document Converter

लखनपुर टोल प्लाजा या वसूली का अड्डा–सुविधाएं नदारद, जाम से बेहाल यात्री

कठुआ, 14 अक्टूबर। जम्मू–कश्मीर के प्रवेशद्वार लखनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर बदइंतजामी के चलते यात्रियों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि आठ रास्तों में से महज चार बूम बैरियर वाले रास्तों को ही चालू रखा गया है। इन रास्तों से छोटी कारा. से लेकर बड़े मालवाहक और ओवरलोड वाहन तक एक साथ निकाले जा रहे हैं। नतीजतन वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद टोल प्लाजा की व्यवस्था में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है।

हैरानी की बात यह है कि यात्रियों से निर्धारित टोल शुल्क पूरा वसूला जा रहा है लेकिन उन्हें सुचारु यातायात और बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। टोल प्लाजा के आसपास पिछले करीब छह महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इससे जम्मू–कश्मीर में प्रवेश करने और प्रदेश से बाहर जाने वाले वाहन चालकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोल प्लाजा पर थोड़ी–सी बारिश होने पर जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। इससे वाहनों की आवाजाही और प्रभावित होती है तथा जाम की लंबाई बढ़ जाती है। सीमित रास्तों पर सभी प्रकार के वाहनों का दबाव होने के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। सवाल यह है कि जब प्रदेश के प्रमुख प्रवेशद्वार पर ही ऐसी स्थिति है तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावों का क्या औचित्य रह जाता है?

लखनपुर टोल प्लाजा से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार के अधिकारी भी रोजाना गुजरते हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग एक–दूसरे पर जिम्मेदारी

डालते नजर आते हैं जबकि आम जनता जाम और अव्यवस्था का खामियाजा भुगत रही है। लखनपुर जम्मू–कश्मीर का प्रमुख प्रवेशद्वार है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों और अन्य यात्रियों का केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करते ही इस तरह की अव्यवस्था से सामना होना जम्मू–कश्मीर की छवि और पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यात्रियों का कहना है कि प्रवेशद्वार पर बेहतर यातायात प्रबंधन और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मामले का कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य या टोल प्लाजा की व्यवस्था ठेकेदार की जिम्मेदारी है तो उसके काम की समीक्षा कर लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि व्यवस्था की जिम्मेदारी एनएचएआई के अधिकारियों की है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। लोगों ने मांग की है कि सभी रास्तों को निर्धारित मानकों के अनुरूप दुरुस्त कर चालू किया जाए, जलभराव की समस्या दूर की जाए और निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। यात्रियों का सवाल है कि जब टोल शुल्क पूरा लिया जा रहा है तो उन्हें सुविधाएं देने में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारी इस समस्या का समाधान कब तक करते हैं या लखनपुर का टोल प्लाजा यूं ही बदइंतजामी और जाम के लिए चर्चा में बना रहेगा।

अंडर–17 बैडमिंटन में जम्मू और रामबन का शानदार प्रदर्शन

कठुआ, 14 अक्टूबर। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में अंडर–17 लड़कियों की अंतर–जिला संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों की खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन पूल ए और पूल बी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह बनाने के लिए दमदार प्रदर्शन किया। पूल ए में रामबन ने रियासी को 2–0 और कठुआ को 2–1 से हराया, जबकि उधमपुर ने कठुआ और रियासी दोनों टीमों को 2–0 से शिकस्त दी। वहीं कठुआ ने रियासी को 2–0 से पराजित कर जीत दर्ज की। पूल बी में जम्मू की टीम का दबदबा रहा। उसने राजौरी, पुंछ और सांबा को लगातार तीन मुकाबलों में 2–0 से हराया। पुंछ ने सांबा को 2–1 से मात देने के बाद राजौरी को 2–0 से पराजित किया। वहीं सांबा ने राजौरी को 2–0 से हराकर जीत हासिल की। यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को संभागीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान कर रही है। प्रतियोगिता का समापन 15 अक्टूबर को होगा। अंतिम दिन दो सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद फाइनल खेला जाएगा जिसमें खिताब के लिए टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।

इंडिया गठबंधन की चार मांगों का समर्थन, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की भी उठाई आवाज

पूर्व मंत्री बाबू सिंह की अध्यक्षता में नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

कठुआ, 14 अक्टूबर। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी ने इंडिया गठबंधन की ओर से उठाई गई चार प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए जम्मू–कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और इसके विशेष दर्जे की बहाली की मांग भी उठाई है। बुधवार को पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री बाबू सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और जम्मू–कश्मीर के राजनीतिक भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में शामिल चार प्रमुख मांगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया।

इन मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी संरक्षण देने वाले वर्ष 2023 के कानून को निरस्त करने की मांग शामिल है। इसके अलावा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा कथित तौर पर हटाए गए 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग भी उठाई गई है। इंडिया गठबंधन की अन्य मांगों में सभी चुनावों में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था बहाल करना तथा पिछले दो वर्षों में हुए उन विधानसभा चुनावों को रद्द करना शामिल है जिनमें गठबंधन के अनुसार वोट चोरी के ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। विपक्षी गठबंधन ने इन मुद्दों को चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताआ. के अधिकारों से जुड़ा विषय बताते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू–कश्मीर से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता दी गई। पार्टी ने जम्मू–कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विशेष दर्जे की बहाली की मांग का समर्थन किया। राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा जम्मू–कश्मीर में निर्वाचित सरकार को अधिक संवैधानिक अधिकारों के साथ काम करने तथा क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है जबकि विशेष दर्जे की मांग अनुच्छेद 370 से जुड़े संवैधानिक बदलावों के संदर्भ में आती है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी सुधारों से जुड़ी मांगों के साथ–साथ जम्मू–कश्मीर के राज्य दर्जे और विशेष दर्जे के मुद्दों पर भी अपना समर्थन व्यक्त किया।

फेयरडील ग्रुप ने लॉन्च की टाटा सिएरा डीएआरके और नई टाटा एरिस

जम्मू। जम्मू–कश्मीर के प्रमुख टाटा मोटर्स डीलर नेटवर्क फेयरडील ग्रुप ने कुंजवानी स्थित फेयरडील मोटर्स और टॉप शेरखानिया स्थित फेयरडील ऑटोमोटर्स में टाटा सिएरा डीएआरके और नई टाटा एरिस को लॉन्च किया।

कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, जम्मू डॉ. अरुण कुमार मनहास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर फेयरडील ग्रुप के प्रबंध निदेशक सलीम बख्शी, निदेशकगण और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

टाटा सिएरा डीएआरके को आकर्षक ब्लैक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। वहीं, नई टाटा एरिस में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार तकनीक और उन्नत सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं।

कंपनी के अनुसार, सिएरा डीएआरके की शुरूआती एक्स–शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये, जबकि टाटा एरिस की शुरूआती कीमत 5.29 लाख रुपये रखी गई है। फेयरडील ऑटोमोटर्स के महाप्रबंधक राहुल सलाथिया ने कहा कि दोनों वाहन ग्राहकों को आधुनिक डिजाइन, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा का आकर्षक संयोजन प्रदान करेंगे।

सिविल डिफेंस जम्मू ने केंद्रीय विद्यालय बंतलाब में जागरूकता शिविर लगाया

प्राथमिक उपचार, अग्निशमन और सीपीआर का दिया प्रशिक्षण

जम्मू। सिविल डिफेंस जम्मू की ओर से केंद्रीय विद्यालय बंतलाब में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल डिफेंस जम्मू के

उप नियंत्रक डीएसपी जिया–उल–हक की देखरेख में आयोजित हुआ। इसमें सिविल डिफेंस के उप मुख्य वार्डन आर. विजय मागोत्रा ने समन्वय किया।

शिविर के दौरान विद्यालय के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार, आग बुझाने, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) और आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने की तकनीकों के बारे में जानकारी देने के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

केंद्रीय विद्यालय बंतलाब के प्रिंसिपल मनोज कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए सिविल डिफेंस जम्मू के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर आर. विजय मागोत्रा ने प्राकृतिक आपदाओं, आग लगने, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों में सिविल डिफेंस वार्डनों एवं स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया देने और लोगों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण तथा जागरूकता बेहद जरूरी है।

शिविर का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना था।

बसपा में शामिल हुई महिलाओं का पार्टी में किया गया स्वागत

आरएस पुरा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बुधवार को आर एस पुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बैठक के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन राणा तथा पार्टी के अन्य लोगों ने शामिल हुई महिलाओं का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को नई दिशा एवं मजबूती मिलेगी। इस मौके पर बसपा के जिला अध्यक्ष तरसेम लाल, सवरन लता, खंड अध्यक्ष जोगिंदर लाल, सहित पार्टी के अन्य लोग भी मौजूद रहे।

इस मौके पर बसपा के प्रदेश प्रमुख दर्शन राणा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह की बैठकों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है और उसी के तहत आरएस पुरा–जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बैठक का आयोजन कर बड़ी संख्या में महिलाओं को बसपा के साथ जोड़ा गया है। इस मौके पर पार्टी के अन्य लोगों ने भी अपने–अपने विचार रखे।

भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान मिल रही है: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का संगीत, नृत्य, सिनेमा और खान–पान देश को दुनिया भर के समाजों से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान मिल रही है। 14–16 अक्टूबर तक विज्ञान भवन में आयोजित बृहत्तर भारतरू दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनश में शामिल लोगों के लिए भेजे गए एक लिखित संदेश में मोदी ने कहा कि स्मारकों को संरक्षित करने के अलावा, सरकार श्ज्ञान भारतमश पहल के ज़रिए भारत की पांडुलिपि विरासत को भी संरक्षित कर रही है।

केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया।

मोदी ने कहा कि विदेशों से प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के प्रयासों को ष्नई गतिष मिली है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ती पहचान मिल रही है। संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। यह सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक विरासत और सीमाओं से परे उसकी व्यापक सभ्यतागत विरासत पर केंद्रित है।

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। यह सम्मेलन दुनिया के साथ भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए अलग–अलग देशों के प्रतिनिधियों, राजदूतों और विद्वानों को एक साथ लाता है। आईजीएनसीए ने बताया कि यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी (जिसे बृहत्तर भारत परिषद के नाम से भी जाना जाता है) की शताब्दी का भी प्रतीक है।

प्रांतीय प्रधान एजेकेपीए ने नवनियुक्त संभागीय आयुक्त जम्मू का किया स्वागत

उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन (ए.जे.के.पी.ए.) के प्रांतीय अध्यक्ष शाम सरूप ने अपनी टीम, केंद्र शासित प्रदेश के आयोजक, एजेकेपीए किश्तवाड़ के जिला अध्यक्ष और एजेकेपीए रियासी के जिला अध्यक्ष के साथ बुधवार को नवनियुक्त संभागीय आयुक्त जम्मू से मुलाकात की।

इस अवसर पर, प्रांत अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त को उनके नए पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक स्वागत और बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने उनके सफल और फलदायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

यह बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई, जो संघ की सद्भावना और मंडल प्रशासन के साथ रचनात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इसी बीच, प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू प्रांत में पटवार समुदाय के सामने आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जम्मू और सहायक आयुक्त

(मध्य) जम्मू से भी मुलाकात की।

विचार–विमर्श के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिन प्रमुख मुद्दों पर विशेष जोर दिया उनमें समय पर पटवार बिरादरी के योग्य सदस्यों के लिए समय पर डीपीसी की बैठकें सुनिश्चित करना, गिरदावरों से संबंधित लंबित समायोजन आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, सेवा संबंधी मामलों में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठता सूची की तैयारी और अंतिम रूप देने में तेजी लाना, जम्मू प्रांत में डीपीसी के संचालन में कश्मीर प्रांत में अपनाए जाने वाले स्थापित पैटर्न के अनुरूप समानता सुनिश्चित करना आदि हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने दोनों प्रांतों में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समान पदोन्नति ढांचे की पुरजोर वकालत की तथा इस बात पर जोर दिया कि जम्मू प्रांत के पटवार समुदाय को कश्मीर प्रांत के अपने समकक्षों के समान, समान विचार और समय पर कैरियर में प्रगति का अधिकार है। एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की कि संभागीय प्रशासन इन वास्तविक चिंताओं को दूर करने और पटवार बिरादरी के पेशेवर हितों की रक्षा के लिए उचित और समय पर उपाय करेगा।

ए.जे.के.पी.ए. जम्मू के संभागीय आयुक्त को उनके सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है और पटवार समुदाय के कल्याण, एकता और पेशेवर गरिमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं–डीसी राजेश शर्मा

कठुआ, 14 अक्टूबर। जिला कठुआ में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त राजेश शर्मा ने डीसी कार्यालय परिसर में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कचरे के उचित संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में मौजूदा कचरा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लेते हुए कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने कचरा प्रबंधन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए थोक कचरा उत्पादकों की पहचान करने और उनके द्वारा उत्पन्न कचरे

के उचित प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित ठोस कचरा प्रबंधन मानकों का पालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक इकाइयों सहित सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को कचरे के निस्तारण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

राजेश शर्मा ने कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग–अलग करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने, निगरानी तंत्र को प्रभावी करने तथा आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान तेज करने पर बल दिया। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। बैठक में एडीसी कठुआ सचिन जम्वाल, सीपीओ रंजीत ठाकुर, एसीपी अजीत कुमार, एओ अखिल कुमार, नगर परिषद कठुआ के सीईओ अमित शर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

टैलेंट पर संकट

माइक्रोसॉफ्ट और सात अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई अमेरिका की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं में एक बुनियादी विरोधाभास को उजागर करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर और एडवांस्ड कंप्यूटिंग में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध देश, विदेशी कर्मचारियों के प्रति बढ़ती शत्रुता से प्रभावित अपनी आव्रजन नीति के साथ असाधारण प्रतिभा की अपनी मांग में आसानी से तालमेल नहीं बिठा सकता है। यह विवाद भ्—1ठ वीजा कार्यक्रम पर केंद्रित है, जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विदेशों से कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। प्रशासन का आरोप है कि कंपनियों ने घरेलू कर्मचारियों की कीमत पर इस प्रणाली का फायदा उठाया है।

उप–राष्ट्रपति जेडी वेंस ने लक्षित कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को रखने का आरोप लगाया है, जबकि श्रम विभाग ने स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम के तहत उनके आवेदनों की प्रक्रिया रोक दी है, जो रोजगार–आधारित ग्रीन कार्ड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिकी कर्मचारियों की रक्षा करना एक जायज उद्देश्य है। कंपनियों को वेतन कम करने या रोजगार संबंधी दायित्वों से बचने के लिए आव्रजन नियमों में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आरोपों के लिए सबूत की जरूरत होती है। एक ही समय में होने वाली छंटनी और वीजा आवेदन अपने आप में यह साबित नहीं करते हैं कि विदेशी कर्मचारियों ने अमेरिकियों की जगह ले ली है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसके हालिया भ्—1ठ आवेदनों में से अधिकांश मौजूदा कर्मचारियों से संबंधित थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त लोगों को अमेरिकी सहयोगियों के बराबर वेतन मिलता है।

इन दावों की जांच होनी चाहिए, जैसा कि सरकार के आरोपों की भी होनी चाहिए। विदेशी पेशेवरों को ष्बंधुआ मजदूरष् बताने पर वेंस की आलोचना भी हुईहैय नई दिल्ली ने इस शब्दावली को बेहद अपमानजनक बताया है। वेंस ने अपनी कथित टिप्पणियों में भारतीयों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया और न ही किसी राष्ट्रीयता का नाम लिया। उनका तर्क अमेरिकी नियोक्ताओं द्वारा विदेशी श्रम के कथित शोषण से संबंधित था। इसके परिणाम केवल उन कंपनियों तक सीमित नहीं रहे जिनका नाम लिया गया था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता पर निर्भर हैं। आप्रवासियों ने सिलिकॉन वैली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति शामिल है। उनके अवसरों को सीमित करने से कुछ घरेलू कर्मचारियों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन इससे विशेष पद खाली रह सकते हैं, भर्ती की लागत बढ़ सकती है और प्रतिभाशाली पेशेवरों को कहीं और अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह एक रणनीतिक भूल होगी।

कनाडा और यूनाइटेड किंगडम कुशल प्रवासियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता में भारी निवेश कर रहा है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आव्रजन प्रणाली को अनिश्चित बनाता है, तो कंपनियां अनुसंधान टीमों और निवेश को स्थानांतरित कर सकती हैं। हो सकता है कि इससे होने वाला नुकसान तुरंत रोजगार के आंकड़ों में न दिखे, लेकिन धीरे–धीरे यह अमेरिका की कॉम्पिटिटिव बढ़त को कम कर सकता है। प्रशासन को बड़ी कंपनियों से जवाबदेही मांगने का हक है। लेकिन अमेरिकी मजदूरों का बचाव करने का मतलब अंतरराष्ट्रीय टैलेंट को बाहर रखना नहीं है। मकसद ऐसा लेबर मार्केट होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयर मजदूरों का शोषण न कर सकें, चाहे उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, और इमिग्रेशन नियम साफ तौर पर तय आर्थिक जरूरतों को पूरा करें। अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप कभी भी सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर पैदा हुए टैलेंट पर निर्भर नहीं रही है। इसे बनाए रखने के लिए भरोसेमंद तरीके से नियमों को लागू करना, निष्पक्ष कॉम्पिटिशन और ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम जरूरी है जो बिना शोषण के काबिलियत को बढ़ावा दे। स्किल्ड माइग्रेशन को राजनीतिक टकराव का मुद्दा बनाने से शायद संरक्षणवादी सोच को संतुष्टि मिले, लेकिन इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की संभावना कम ही है।

नरेन्द्र मोदी की सियासत के 25 साल: भारतीय राजनीति में कैसे स्थापित हुआ 'मोदी मार्ग'?

उमेश चतुर्वेदी

सात अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कोई नहीं सोच रहा था कि मोदी एक साल का भी कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। राजनीतिक जानकारों और गुजरात के लोगों की इस सोच के पीछे कुछ खास वजहें भी थीं। मोदी के गुजरात का सरदार बनने से पहले के पांच वर्षों में राज्य में एक–एक करके चार मुख्यमंत्री आए और चले गए थे। मोदी राज्य के किसी ताकतवर जाति समुदाय से भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। हां, पर्दे के पीछे की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर वे स्थापित थे। इतना ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्यों के बीजेपी प्रभारी के रूप में भी अपनी सियासी समझ का भी वे लोहा मनवा चुके थे। लेकिन वक्त के साथ, मोदी ने सभी आशंकाओं को ना सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि चौथाई सदी तक लगातार सत्ता का केंद्र बिंदु रहने वाले वाली शख्सियत भी बन चुके हैं। इसके पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु के नाम देश में सबसे लंबे समय यानी करीब 23 साल सत्ता संभालने का रिकॉर्ड था। मोदी उस रिकॉर्ड से भी काफी आगे बढ़ चुके हैं।

हाल के दिनों में एक वरिष्ठ हिंदी पत्रकार मोदी मार्ग की अवधारणा देकर आलोचनाओं के केंद्र में हैं। मोदी मार्ग की चर्चा हो तो वामपंथी तो सांड़ की तरह भड़केंगे ही, वे समाजवादी भी वरिष्ठ पत्रकार के आलोचक हो गए हैं, जो कभी उनके सहयोगी रहे या वे उनके साथी रहे। बेशक मोदी मार्ग की इन दिनों आलोचना हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब नरेंद्र मोदी का अपना और उनके दौर के भारत का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित तौर पर मोदी मार्ग या मोदीत्व की अवधारणा को भी स्वीकार किया जाएगा। किसी शख्सियत के जरिए शुरू पंथ या वैचारिक धारा को उसके जीवन काल में सर्व मान्यता और स्वीकार्यता कम ही मिल पाती है। लेकिन जब वही शख्सियत इतिहास की धारा में विलीन हो जाती है, तो उसकी दिखाई राहों को पंथ का दर्जा मिलने लगता है। गांधी बेशक अपनी जिंदगी में ही महात्मा के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनके कई प्रयोगों की उसी तरह आलोचनाएं होती रहीं, जैसे आज

मोदी के वैचारिक विरोधी उनके तमाम कदमों की कटु आलोचनामें लीन रहते हैं। वैसे भी लोकतांत्रिकक दौर के भारतीय समाज की एक धारा रही है। शुरू में वह पदधारकों का शुरू में स्वागत करता है, बाद में उसका विरोधी हो जाता है। लेकिन वही शख्सियत जब इतिहास में समाहित हो जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ समाज उसका घोर प्रशंसक हो जाता है। बीजेपी की ही राजनीति का उदाहरण इस संदर्भ में ले सकते हैं। एक दौर में बीजेपी विरोधियों की नजर में अटल उदार थे, जबकि आडवाणी कट्टर। लिहाजा आडवाणी लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे। लेकिन जैसे ही अटल युग की समाप्ति हुई और मोदी युग की ओर बीजेपी बढ़ चली, आडवाणी उन्हीं विरोधियों की नजर में आदर के पात्र होते गए और मोदी के कटु आलोचकों की संख्या बढ़ती गई। कुछ इसी अंदाज में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई अन्य नेता उभरा तो हो सकता है कि मोदी बीजेपी विरोधियों की नजर में ही प्रशंसा का पात्र बन जाएं और बीजेपी का भावी नेता आडवाणी और मोदी की तरह आलोचनाओं के केंद्र में आ जाए। सत्ता की राजनीति में मोदी की यात्रा पर निगाह डालते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती खुद की स्वीकार्यता बढ़ाना रही। जिस तरह चौथाई सदी से वे सत्ता के केंद्र में हैं, उसे देख कह सकते हैं कि इसमें वे कामयाब रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सबसे ज्यादा समय तक सत्ता को खुद के इर्द–गिर्द केंद्रीकृत करने में भी सफल रहे हैं। आज भारत की केंद्रीय सत्ता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उन्हीं के इर्द–गिर्द केंद्रित है और उन्हीं से शक्ति ग्रहण करता है।

यह मोदी का दुर्भाग्य रहा कि उनके गुजरात की सत्ता संभालने के महज छह महीने बाद ही राज्य को गोधरा कांड के चलते भयानक सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा। गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में 1044 लोगों के मारे गए , जबकि 2548 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 223 लोग लापता बताए गए। दंगों के सात साल बीतने के बाद सरकार के ही अनुसार, लापता लोगों की संख्या कुछ बढ़ गई। इन दंगों के बाद नरेंद्र मोदी विशेषकर कांग्रेस और वामपंथी दलों के निशाने पर आ गए। देश के वामपंथी सोच से प्रभावित स्वयंसेवी संगठनों ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा खोल दिया। एक तरह से मोदी को राजनीतिक घृणा का पात्र बनाने की कोशिश की गई। उनके चरित्र हनन तक की कोशिशें हुईं। गुजरात दंगों के साथ ही इशरत जहां मुठभेड़ कांड को लेकर उनके खिलाफ सीबीआई जांच हुई। सीबीआई के समक्ष बतौर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उन्हें कई बार घंटों तक उपस्थिति जतानी पड़ी और बतौर मुख्यमंत्री उन्हें घंटों तक सीबीआई के अच्छे–बुरे सवालों का सामना करना पड़ा। गुजरात दंगों के दाग के चलते एक दौर में उन्हें अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया। इस बिंदु पर देखें तो मोदी का जीवट व्यक्तित्व उभरता है। कह सकते हैं कि तिरस्कार और आलोचनाओं से वे ताकत ग्रहण करते हैं, कुछ–कुछ मिथकीय पात्र बालि की तरह। जिस तरह बालि के सामने आए उसके विरोधियों की आधी ताकत बालि में ही समाहित हो जाती थी, मोदी कुछ उसी तरह विरोधियों की आलोचनाओं से ताकत ग्रहण करते हैं और अपनी राह बनाते रहते हैं। तीखे और अपमानजनक विरोध से जीवट से जीवट वाली शख्सियतें टूट जाती हैं, मोदी की ना सिर्फ कटु आलोचना हुई या हो रही है, उन्हें सार्वजनिक मंचों से घटिया, अश्लील और फूहड़ गालियां दी जा रही हैं। अतीत में उन्हें चरित्र हनन की सीमा तक बदनाम करने की कोशिशें हुईं। लेकिन मोदी रुके नहीं। कभी पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले मोदी लगातार आगे बढ़ते रहे।

गुजरात में जब चीजें पटरी पर आनी शुरू हुईं तो उन्होंने राज्य के विकास को लेकर अपना मॉडल पेश किया। जिसे कालांतर में देश ने उसे 'गुजरात मॉडल' के नाम से जाना। 'गुजरात मॉडल' के विकास और इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रवासियों और निवेशकर्ताओं को लुभाने के लिए उन्होंने 'वायब्रेंट गुजरात' नाम से आयोजन शुरू किए। जिसे देखते ही देखते राज्य की जनता ने तो अपनाया ही, प्रवासियों ने भी हाथोंहाथ लिया। इसी का असर रहा कि जिस राज्य में महज पांच साल में चार मुख्यमंत्री आए और गए, उसी राज्य में मोदी ने साढ़े बारह साल से अधिक वक्त तक सत्ता संभालने का रिकॉर्ड बनाया। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी ख्याति राज्य से बाहर की सीमाओं तक पैठ बना चुकी थी या बना रही थी। इसका ही नतीजा रहा कि 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों के वक्त राष्ट्रीय मीडिया के एक हिस्से ने मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब कहा जा रहा था कि गुजरात इस बार सिर्फ अपने मुख्यमंत्री का ही नहीं, बल्कि देश के भावी प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर रहा है। मोदी की राजनीतिक यात्रा जातिवादी राजनीति का जवाब भी है। कांग्रेस के प्रथम परिवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को छोड़ दें तो आज के ज्यादातर बड़े राजनेता कहीं न कहीं सिर्फ अपनी जातियों के नेता हैं या उनकी राजनीतिक बुनियाद का आधार उनकी जाति है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता में उनकी जाति का कोई आधार नहीं है।

मोदी ने अपने लंबे शासन काल में ढरों उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की वैश्विक मंच पर बदली छवि। उनके शासनकाल में भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार हुआ है। मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर देश को बहुत गति दी है। मोदी कहते हैं कि उनकी नजर में सिर्फ चार जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। मोदी के लंबे शासन काल में इन चारों ही वर्गों का ध्यान ठीक से रखने की कोशिशें बढ़ी हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगर बन चुका है, तो इसके पीछे उनका नजरिया भी है। कृषि में साढ़े चार प्रतिशत सालाना की विकास दर हासिल की जा चुकी है, बीजेपी के एजेंडे के तहत अयोध्या में राममंदिर बन चुका है, कश्मीर को अलग–थलग करने वाले संविधान के विशेष अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया जा चुका है। मोदी के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाने बैठें तो पूरी रात गुजर जाएगी। बस मोटे तौर पर कह सकते हैं कि मोदी राज में देश ने अपना खोया गौरव हासिल करने की दिशा में एक मजबूत कदम जरूर बढ़ाया है।

अनियंत्रित भीड़ को 'शिव बारात' की उपमा देकर राहुल गांधी ने हिंदू भावनाओं को पहुँचाई ठेस!

नीरज कुमार दुबे

भले ही राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में अपने राजनीतिक मार्च को 'शिव बारात' कहकर केवल एक उपमा दी हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान शिव की बारात जैसे पवित्र धार्मिक प्रसंग को राजनीतिक विरोध–प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करना उचित था? जिस बारात का संबंध देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के दिव्य विवाह से है, उसे एक राजनीतिक आंदोलन का नाम देते समय क्या उसकी धार्मिक गरिमा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था?

हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के मार्च के दौरान कहा था कि यह शिव की बारात है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उन्होंने आंदोलन की तुलना भगवान शिव के तांडव से भी की थी। उनका आशय आंदोलन को स्वतःस्फूर्त और सबके लिए खुला बताना था। लेकिन इसी बयान ने धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर विवाद खड़ा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए सार्वजनिक माफी की माँग की है। कैलेंडरदेखें

देखा जाये तो यहाँ सवाल केवल एक उपमा का नहीं, बल्कि उस धार्मिक प्रतीक के अर्थ का है जिसे भारतीय समाज में विशेष श्रद्धा के साथ देखा जाता है। राहुल गांधी को शायद पता नहीं कि शिव बारात कोई सामान्य जुलूस नहीं है।

शिवपुराण की रुद्रसंहिता के पार्वतीखंड में भगवान शिव की विवाह–यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। अध्याय 40 में शिव की बारात का प्रसंग है। इसके बाद विवाह की तैयारियों, शिव के हिमालय पहुँचने और विवाह–संस्कार का वर्णन आगे के अध्यायों में आता है। अध्याय 48 में पुरोहितों द्वारा तिथि आदि बताए जाने और शुभ समय आने के बाद विवाह–संस्कार प्रारंभ होने का उल्लेख है।

शिव बारात का धार्मिक महत्त्व इसी दिव्य विवाह से जुड़ा है। इसमें शिवगणों, नंदी, देवताओं और ऋषियों की सहभागिता का वर्णन मिलता है। लोकपरंपरा में भूत–प्रेत और विचित्र रूप वाले गणों के चित्रण ने इस बारात को एक विशिष्ट पहचान दी है। यह शिव के उस स्वरूप की याद दिलाता है जो बाहरी रूप, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा की सीमाओं से परे है। इसीलिए शिव बारात को केवल लोगों की भीड़, नारेबाजी या किसी राजनीतिक आंदोलन के लिए सुविधाजनक उपमा मान लेना श्रद्धालुओं को असहज कर सकता है। धार्मिक प्रतीक की अपनी गरिमा होती है और उसका इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जा रहा है, यह महत्त्वपूर्ण है।

साथ ही यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या शिव बारात किसी भी दिन निकल सकती है? देखा जाये तो हिंदू धर्म में धार्मिक पर्व, विवाह–संस्कार और शोभायात्रा के अपने अलग–अलग नियम और परंपराएँ हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख पर्व है। इस अवसर पर देशभर में शिव बारात निकाली जाती है और शिव–पार्वती विवाह की झाँकियाँ सजाई जाती हैं। वहीं, शास्त्रोक्त विवाह–संस्कार में तिथि, पंचांग और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्त्व होता है। शिवपुराण में भी शिव–पार्वती विवाह के प्रसंग में तिथि और शुभ समय का उल्लेख मिलता है। साथ ही परम्परागत रूप से शिव बारात महाशिवरात्रि के दिन ही निकाली जाती है और देश में शायद ही किसी अन्य दिवसों पर शिव बारात का आयोजन होता हो। सामान्य धार्मिक शोभायात्रा किसी स्थानीय उत्सव या मंदिर की परंपरा के अनुसार अन्य अवसरों पर भी निकाली जा सकती है। इसके विपरीत, यदि आयोजन को विधिवत शिव–विवाह या किसी विशिष्ट पर्व का शास्त्रोक्त अनुष्ठान बताया जा रहा है, तो संबंधित तिथि, पूजा–विधान, मुहूर्त और परंपरा का पालन अपेक्षित है।

साथ ही राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि भगवान शिव की बारात में धक्के मारने या कोहनी से दूसरों को मारने या किसी को कॉलर पकड़ कर पीछे धकेलने की कोई परम्परा नहीं है। शिव बारात में भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का भाव होता है, न कि किसी को धक्का देने या कोहनी मारकर आगे बढ़ने का। भले ही राहुल गांधी की उपमा का उद्देश्य अपने राजनीतिक मार्च को सबके लिए खुला बताना रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए भगवान शिव की बारात जैसे पवित्र प्रसंग को ही क्यों चुना गया? क्या एक राजनीतिक आंदोलन में शामिल भीड़ की तुलना शिव बारात से करना उचित था? और क्या ऐसी तुलना शिव बारात की धार्मिक छवि को एक अनियंत्रित भीड़ के रूप में प्रस्तुत नहीं करती?

बहरहाल, राहुल गांधी के इस बयान ने धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल और सनातन परंपराओं के प्रति संवेदनशीलता को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। देखा जाये तो लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन उस विरोध को व्यक्त करने के लिए करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल करते समय उनकी गरिमा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।

Created by Universal Document Converter

गरीबी के साथ आर्थिक असमानता दूर करने का लक्ष्य हो

ललित गर्ग

भारत एक ओर जहां लगातार तेज ग्रोथ करते हुए बीते दिनों जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, तो वहीं उपलब्धियों का सिलसिला जारी है और दुनिया इसका लोहा मान रही है। अब एक और खुश करने वाली रिपोर्ट आई है, जो विश्व बैंक ने जारी की है, जिसमें भारत में अत्यधिक गरीबी में आई उल्लेखनीय कमी की रोशनी है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022–23 में यह दर 5.3 प्रतिशत रह गई है, जो वर्ष 2011–12 में 27.1 फीसदी थी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार भारत ने लगभग एक दशक से कुछ कम समय में 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, जो पैमाने और गति के मामले में उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक उपलब्धि कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शासन के ग्यारह स्वर्णिम वर्षों में गरीबी को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है, गरीबों के संघर्षों और उनकी चिंताओं को सुनकर, उन्हें गरीबी से बाहर आने में मदद करके और अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके उन्होंने गरीब उन्मूलन की योजनाओं को जमीन पर उतारा है। मोदी सरकार ने गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। उनकी दृष्टि में गरीबी को खत्म करना सिर्फ गरीबों की मदद करना नहीं है – बल्कि हर महिला और पुरुष को सम्मान के साथ जीने का मौका देना है।

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी पहलों, तेज आर्थिक सुधारों और जरूरी सेवाओं तक सबकी पहुंच का ही यह नतीजा है कि गरीबी दिन–ब–दिन तेजी से घट रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार में वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2005–06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर 2019–21 में 16.4 प्रतिशत और 2022–23 में 15.5 प्रतिशत हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर फोकस पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन–धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच को बढ़ाया है।

डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी), डिजिटल समावेश और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने अंतिम जन तक लाभों की पारदर्शिता और तेज वितरण सुनिश्चित किया है। इससे 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी पर पार पाने में मदद मिली है। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संबल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उनका बेहतर क्रियान्वयन किया है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। पूरे भारत में अत्यधिक गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें प्रमुख राज्यों ने गरीबी में कमी लाने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांच बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में 2011–12 में देश के 65 फीसदी अत्यंत गरीब लोग थे। इन पांच राज्यों ने ही 2022–23 तक गरीबी कम करने में दो–तिहाई का योगदान दिया है।

विश्व बैंक ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत से गरीबी उन्मूलन की योजनाओं एवं सोच से प्रेरणा लेने की बात कही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की 45 प्रतिशत आबादी गरीबी में है। भारत की गरीबी दर 5.3 प्रतिशत और पाकिस्तान की 42.4 प्रतिशत है। इसका सबसे बड़ा कारण पाक अपना सारा ध्यान आतंकवाद एवं आतंकवादियों के पोषण पर देता है, गरीबी दूर करना उसकी योजनाओं एवं नीतियों में दूर–दूर तक नहीं है। इसीलिये भारत ने वैश्विक मंचों पर पाक पर यह आरोप भी लगाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय सहायता का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे पाक को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा करें, क्योंकि इसका उपयोग आम लोगों के कल्याण के बजाय सैन्य खर्च और आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है। हाल के पाहलगाम हमले के बाद भारत ने इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाया, जिसमें उसने पाक के सैन्य बजट में 18 प्रतिशत वृद्धि और सामाजिक कल्याण पर कम खर्च को उजागर किया। गरीबी किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन है। यह न केवल अभाव, भूख और पीड़ा का जीवन जीने की ओर ले जाती है, बल्कि मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के आनंद का भी बड़ा अवरोध है। पाक में यही स्थितियां देखने को मिल रही है।

आजादी के अमृत काल में सशक्त भारत एवं विकसित भारत को निर्मित करते हुए गरीबमुक्त भारत के संकल्प को भी आकार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार ने वर्ष 2047 के आजादी के शताब्दी समारोह के लिये जो योजनाएं एवं लक्ष्य तय किये है, उनमें गरीबी उन्मूलन के लिये भी व्यापक योजनाएं बनायी गयी है। विगत ग्यारह वर्ष एवं मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऐसी गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे भारत के भाल पर लगे गरीबी के शर्म के कलंक को धोने के सार्थक प्रयत्न हुए है एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों को ऊपर उठाया गया है। निश्चित रूप से इस उपलब्धि में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों मसलन आर्थिक विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। निस्संदेह, इसने सबसे गरीब तबके के लोगों की आय बढ़ाने में मदद की है। निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिजली, शौचालयों और आवास तक इस तबके की पहुंच बढ़ाने जैसी पहल ने ग्रामीण और अर्ध–शहरी भारत में जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में योगदान दिया है। लेकिन जहां हम गरीबी उन्मूलन में मिली सफलता पर आत्ममुग्ध हैं तो वहीं समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। गरीबी–अमीरी के बीच के बढ़ते फासले को कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पिछले साल जारी की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि भारत में शीर्ष एक प्रतिशत लोगों की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। वे लोग देश की चालीस फीसदी संपत्ति नियंत्रित करते हैं।

भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, अमीर–गरीब में ऊंच–नीच, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी आदि हैं। एक आजाद मुल्क में, एक शोषणविहीन समाज में, एक समतावादी दृष्टिकोण में और एक कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था में गरीबी रेखा नहीं होनी चाहिए। अब तक यह रेखा उन कर्णधारों के लिए शर्म की रेखा बनी रही है, जिसको देखकर उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। एक बड़ा प्रश्न था कि जो रोटी नहीं दे सके वह सरकार कैसी? जो अभय नहीं बना सके, वह व्यवस्था कैसी? जो इज्जत व स्नेह नहीं दे सके, वह समाज कैसा? गांधी और विनोबा ने सबके उदय एवं गरीबी उन्मूलन के लिए 'सर्वोदय' की बात की। लेकिन राजनीतिज्ञों ने उसे निज्योदय बना दिया था। 'गरीबी हटाओ' में गरीब हट गए। अब तक जो गरीबी के नारे को जितना भुना सकते थे, वे सत्ता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब मोदी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिये सार्थक प्रयत्न कर रही है। मोदी सरकार की तकनीकी प्रेरित सेवाओं में उछाल के चलते, वर्ष 2000 के बाद विकास मॉडल ने गरीब वर्ग को लाभान्वित किया है। निर्विवाद रूप से सामाजिक न्याय के लिये गरीबी कम करने के साथ, कमजोर तबकों के लिये सम्मान, समानता और नीतियों में लचीलापन जरूरी है। वास्तव में गरीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियां न केवल उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाएं। आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का मकसद मुफ्त की रेवड़ियां बांटना न होकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। तभी गरीबी का कुचक्र स्थायी रूप से कम किया जा सकता है।

उनका देविका को लेकर किया गया संघर्ष में मिली कुछ कामयाबी

प्रशासन ने उपलब्ध करवाई प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकांश जानकारी: मट्टू

उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। सामाजिक कार्यकर्ता मोहित मट्टू जिन्होंने कुछ दिन पहले देविका नदी के प्रोजेक्ट को लेकर देविका में मुंडन करवाया था, बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रशासन द्वारा उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया है तथा उन्होंने देविका प्रोजेक्ट जिसके लिए 186.74 करोड़ रूपया आया था, उसके विषय में अधिकांश जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

उन्होंने कहा कि वह सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले थे तथा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। उनका कहना था कि इसमें जो भी कमियां है वह उनके सामने लाई जाएं ताकि उनमें सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य देविका की पवित्रता को बहाल करना था। उधमपुर नगर में 21 वार्ड हैं और सब की गंदगी इसी

में जा रही थी, उसके लिए नगर में 120 किलोमीटर लंबी सीवरेज पाइप बिछाकर गंदगी को देविका से दूर रखना था परंतु इस प्रोजेक्ट में उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

इसके लिए वह संघर्ष कर रहे है और जहां कमियां है वह लोग हम सामने लाएं ताकि उन कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम प्रशासन व सरकार के सामने उठाए जा सके।

बेरोजगारी और सरकारी स्कूलों की बदहाल सुविधाओं पर सरकार जवाब दे: पवन खजुरिया

उधमपुर, 14 अक्तूबर (संजीव शर्मा)। वरिष्ठ नेता पवन खजुरिया ने जम्मू–कश्मीर सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों के दावों पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और सरकारी स्कूलों के खराब बुनियादी ढांचे की स्थिति सरकार की कार्यप्रणाली की गंभीर कमियों को उजागर करती है।

अपने सहयोगियों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पवन खजुरिया ने कहा कि उपलब्धियों का जश्न मनाने का कोई अर्थ नहीं है, जब तक सरकार बेरोजगार युवाओं, विद्यार्थियों और उनके परिवारों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करती।

उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षित युवा आवश्यक योग्यताएं होने के बावजूद रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, रिक्त पदों का नहीं भरा जाना और बार–बार परीक्षाएं आयोजित होने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से लगभग 17,000 रिक्त सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करने तथा लंबित चयन प्रक्रियाओं को निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा करने की मांग की।

खजुरिया ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नौकरी के इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में लगभग 110 करोड़ रुपये एकत्र किए जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने सरकार से इस राशि के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने तथा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने या उसमें पर्याप्त कमी लाने की नीति लागू करने की मांग की।

नशा विरोधी अभियानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता अभियान चलाने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता। युवाओं को नशे और नकारात्मक प्रभावों से दूर रखने के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती निराशा और असुरक्षा का फायदा राष्ट्रविरोधी तत्व उठा सकते हैं, इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

सरकारी स्कूलों की बदहाल

स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए खजुरिया ने रिपोर्टों में सामने आए आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 765 स्कूल भवन असुरक्षित बताए जा रहे हैं, 12,615 स्कूलों में शौचालयों की सुविधा नहीं है, करीब 8,800 स्कूलों में पेयजल की कमी है और लगभग 2,770 स्कूलों की इमारतें बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बच्चे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के दावे किस आधार पर कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और अन्य कर्मचारियों की कमी ने भी सरकारी स्कूलों के कामकाज को प्रभावित किया है, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थिति अधिक चिंताजनक है।

खजुरिया ने मांग की कि स्कूल भवनों की तत्काल सुरक्षा जांच करवाई जाए, असुरक्षित इमारतों की मरम्मत और आवश्यक निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं तथा सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षण स्टाफ, स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और जम्मू–कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है।

पवन खजुरिया ने कहा, कि सरकार को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हुई वास्तविक प्रगति का स्पष्ट हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। केवल प्रचार और उपलब्धियों के दावों से युवाओं तथा विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

इस अवसर पर राज कुमार बुच्चा, पूर्व सरपंच गौतम, राहुल गुप्ता, गुरदयाल खजुरिया, संजय वर्मा, कैप्टन योग राज, विजय कुमार, साहिल बख्शी, रोहित सरमाल, सनी महाजन, नटेश्वर वेद, गगनदीप सिंह (रवि), कुलदीप (थोडु), सुनील शर्मा, अनिल रैन्याल, विक्की चौधरी, अर्जुन गोस्वामी, दीपक ठाकुर, अनिल शर्मा, रोहित सिंह, राघव रैना, रघु रैन्याल, पवन (बब्बी), मखन, मनीष, दीपक, राकेश (राकू), कनव वर्मा सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

एपीएस उधमपुर का दोहरा स्वर्णिम विजय अभियान

उत्तरी कमान इंटर–क्लस्टर हॉकी टूर्नामेंट में बालक एवं बालिका वर्गों में शानदार जीत

उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर ने उत्तरी कमान इंटर–क्लस्टर हॉकी टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बालक एवं बालिका, दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर द्वारा किया गया, जिसमें उत्तरी कमान के क्लस्टर–ए और क्लस्टर–वी के विजेता विद्यालयों के बीच चौंपियनशिप के लिए रोमांचक मुकाबले हुए।

बालक वर्ग में शानदार जीत

बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर (क्लस्टर–ए) ने आर्मी पब्लिक स्कूल, मथुरा (क्लस्टर–वी) के विरुद्ध दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 3–0 गोल से शानदार विजय प्राप्त की। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट तालमेल, अनुशासित रणनीति और आक्रामक खेल ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

बालिका वर्ग में भी उधमपुर का दबदबा

बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला भी अत्यंत रोमांचक रहा। आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर (क्लस्टर–ए) की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने आर्मी पब्लिक स्कूल, मथुरा (क्लस्टर–वी) को 2–0 गोल से पराजित कर चौंपियनशिप पर कब्जा जमाया। दोनों वर्गों में मिली इस शानदार

सफलता ने विद्यालय की खेल प्रतिभा, टीम भावना और उत्कृष्ट प्रशिक्षण को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया।

मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

समापन समारोह में मुख्य अतिथि कर्नल रत्नदीप खान एसओ–स्कूल्स, 71 सब–एरिया ने विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भूरि–भूरि प्रशंसा की तथा उन्हें पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और खेल भावना की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर की प्राचार्या डॉ. ज्योति बडयाल ने जताया गर्व

इस अवसर पर आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर की प्राचार्या डॉ. ज्योति बडयाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना, टीमवर्क, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक उत्साह को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, उत्तरी कमान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और सौहार्द को सुदृढ़ करना भी इसका महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश का उज्ज्वल भविष्य है। अपनी अदम्य प्रतिभा, कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प के बल पर ये खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इनकी उपलब्धियों पर मुझे अपार गर्व है। प्राचार्या ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, आयोजनकर्ताओं, प्रशिक्षकों, शिक्षा, सहयोगियों तथा प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

आर्मी पब्लिक स्कूल, उधमपुर की इस दोहरी विजय ने विद्यालय की उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। दोनों वर्गों में चौंपियन बनने की यह गौरवपूर्ण उपलब्धि खिलाड़ियों के समर्पण, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यालय की खेल–उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। यह सफलता न केवल विद्यालय परिवार, बल्कि समस्त उधमपुर के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

मेन बाजार की सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो शुक्रवार सुबह 11 बजे दब्बड़ चौक पर धरना देंगे: मगोत्रा

10 दिन का समय देने के बावजूद समस्या बरकरार, दुकानदारों की सुरक्षा और कारोबार पर मंडरा रहा खतरा

उधमपुर, 14 अक्तूबर (संजीव शर्मा)। मेन बाजार ऊधमपुर में जल शक्ति विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत न होने से परेशान दुकानदारों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ऊधमपुर के अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन और संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मुख्य बाजार के कई दुकानदार भी उपस्थित रहे और उन्होंने सड़क की बदहाल स्थिति के कारण हो रही परेशानियों को सामने रखा।

सुमित मगोत्रा ने कहा कि करीब 12 दिन पहले उन्होंने स्वयं मेन बाजार का पैदल दौरा कर दुकानदारों की समस्याएं सुनी थीं और प्रशासन को सड़क की मरम्मत के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद उन्होंने जल शक्ति विभाग के एक्सीयन तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों से भी बातचीत की। अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि सड़क पर पत्थर और कंकड़ डालने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन आज भी व्यापारियों द्वारा सड़क की स्थिति को लेकर गंभीर शिकायतें सामने रखी गई है।

मगोत्रा ने बताया कि सड़क पर बिखरे पत्थरों के कारण वाहनों के टायरों से कंकड़ तेज गति से उछलकर दुकानों के शीशों से टकरा रहे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में

मौजूद एक दुकानदार की दुकान का शीशा भी टूट चुका है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'आज पत्थर लगने से दुकान का शीशा टूटा है, लेकिन अगर यही पत्थर किसी इंसान को लग जाता तो उसका क्या हाल होता? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है ?

उन्होंने कहा कि मेन बाजार शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते है। त्योहारों का मौसम होने के कारण दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद रहती है, लेकिन सड़क पर उड़ती धूल–मिट्टी और बिखरे पत्थरों के कारण व्यापारी परेशान है। ग्राहकों को भी आने–जाने में कठिनाई हो रही है और दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

सुमित मगोत्रा ने कहा कि इस सड़क का काम राजस्थान के ठेकेदार को आवंटित किया गया है। ऐसे में संबंधित विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि ठेकेदार से कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता और समयसीमा में काम पूरा करवाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि जब सड़क की मरम्मत का काम आवंटित है, तो विभाग ठेकेदार से सख्ती से काम क्यों नहीं करवा रहा ? उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को इस मामले में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

मगोत्रा ने स्पष्ट किया कि अब व्यापारियों को और इंतजार नहीं करवाया जा सकता। यदि शुक्रवार सुबह तक सड़क पर पैचवर्क करके वर्क ऑर्डर के अनुसार उचित और समतल सतह तैयार नहीं की गई, तो शुक्रवार सुबह ठीक 11 बजे दब्बड़ चौक पर व्यापारियों के साथ धरना–प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से अपील की कि शुक्रवार की समयसीमा को गंभीरता से लेते हुए सड़क की मरम्मत का काम तत्काल पूरा करवाया जाए, ताकि दुकानदारों और ग्राहकों को राहत मिल सके तथा किसी संभावित दुर्घटना को टाला जा सके।

मगोत्रा ने कहा कि इस मामले को लेकर हम नवनियुक्त जिला आयुक्त से मिलकर बात करेंगे। उनका उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना और उनका समाधान सुनिश्चित करवाना है। उन्होंने दोहराया कि व्यापारी वर्ग की रोजी–रोटी, आम जनता की सुविधा और लोगों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर तब तक आवाज उठाई जाएगी, जब तक सड़क की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो जाता।

Created by Universal Document Converter

पंजाब केसरी ग्रुप, जालंधर की मदद से उधमपुर में 150 जरूरतमंद परिवारों में रजाईयां बांटी गईं: प्रीति खजूरिया

उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के मकसद से एक इंसानी पहल के तहत, पंजाब केसरी ग्रुप, जालंधर की मदद से उधमपुर में 150 जरूरतमंद परिवारों में रजाईयां बांटी गईं।

इस पहल में दया, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज सेवा की भावना दिखी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को अपनापन और आराम मिला।

पूर्व पार्षद अश्विनी और एवं पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया, ने इस भलाई की पहल को मुमकिन बनाने हेतु पंजाब केसरी ग्रुप, जालंधर के सपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जरूरतमंदों की सेवा करना और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे

कहा कि ऐसी पहल न सिर्फ काम की मदद करती हैं बल्कि इंसानियत और सामाजिक मेलजोल के बंधन को भी मजबूत करती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि समाज को जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए एक साथ आना चाहिए, खासकर सर्दियों के महीनों में, जब जरूरी चीजों तक पहुँच और भी जरूरी हो जाती है। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप का उनके सहयोग और समाज की भलाई के लिए उनके कमिटमेंट के लिए शुक्रिया अदा किया।

इस मौके पर मौजूद लोगों में पंजाब केसरी जालंधर के योग गुरु वरिंदर शर्मा, डिंपल सूरी, इकबाल सिंह अरनेजा, सर्वदीप अरनेजा, पंजाब केसरी, उधमपुर से दीपक, सुरजीत सिंह जम्वाल, कांता, गौरजू खजूरिया, परवेज और गुलाम रसूल शामिल थे।

वितरण समारोह में समाज के कमजोर तबकों तक पहुंचने के लिए मिलकर कोशिश करने और कम्युनिटी की हिस्सेदारी की अहमियत पर जोर दिया गया। आयोजक ने इंसानियत से जुड़े काम जारी रखने और जरूरतमंद परिवारों की भलाई के लिए काम करने का अपना कमिटमेंट दोहराया।

सीआरपीएफ 187 बटालियन ने डुडू में आयोजित किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर

250 ग्रामीणों ने चिकित्सा शिविर में करवाई जांच

उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) की 187 बटालियन द्वारा गांव डूडू, जिला उधमपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ गायकवाड सचिन पोपट, द्वितीय कमान अधिकारी 187 बटालियन द्वारा किया गया। के.रि.पु.बल के इस अभियान के तहत दूरदराज के ग्रामीणों पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की मुफ्त चिकित्सा जांच की गई और दवाइयां वितरित की गई। जिसमें डूडू गांव एवं आस–पास के गांवों (लापा, घरकटियास, जखेड, पडेर, किरची) के लगभग 250 ग्रामीणों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया।

इस कार्यक्रम को डॉ. मनमीत कौर बरार, चिकित्सा अधिकारी 187 बटालियन, सुमन पाल डिप्टी कमांडेंट 187 बटालियन, डॉ. प्रदीप चिकित्सा अधिकारी डूडू एवं

पैरामेडिकल स्टाफ सहायक 187 बटालियन, के सहयोग से संचालित किया गया।

इस अवसर पर गायकवाड सचिन पोपट द्वितीय कमान अधिकारी, निरीक्षक अनूप सिंह, निरीक्षक नरेश पुनिया 187 बटालियन केरिपुबल एवं हंसराज पूर्व सरपंच डुडू, सब इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पुलिस पोस्ट डुड, कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। गायकवाड सचिन पोपट द्वितीय कमान अधिकारी 187 बटालियन, केरिपुबल द्वारा चिकित्सा शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इस शिविर का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया गया साथ टी यह भी बताया कि केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल परिचालनिक ड्यूटियों के अलावा सामाजिक एवं मानवीय पहलू से भी कार्य करती है ताकि स्थानीय लोग अच्छे नागरिक बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें।

उपस्थित गणमान्य लोगों का धन्यवाद करते हुए यह भी अवगत कराया गया कि इसी प्रकार चिकित्सा शिविर का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशानुसार समय–समय बटालियन के तैनाती क्षेत्रों में भविष्य में भी किया जाता रहेगा। स्थानीय लोगों को मुफ्त दवाईयां व चिकित्सकीय सलाह मिलने पर लोगों में हर्ष का वातावरण था।

जम्मू में मिशलिन इंडिया का नया स्टोर शुरू, ग्राहकों को मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं!

नई दिल्ली। विश्व की अग्रणी टायर टेक्नोलॉजी कंपनी 'मिशलिन' द्वारा 'महाशक्ती ऑटो' के सहयोग से जम्मू में एक नया 'मिशलिन टायर्स एंड सर्विस' (एमटीएस) स्टोर शुरू किया गया है। यह स्टोर शहर के मुख्य व्यावसायिक केंद्र, गुमत के मुख्य बाजार में स्थित है। इस नए स्टोर के माध्यम मे जम्मू और आसपास के क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए मिशलिन के उत्पाद और सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

एक हजार वर्ग फीट जगह में खुले इस स्टोर में कारों, दोपहिया वाहनों और बड़े वाहनों के लिए मिशलिन के सभी प्रकार के टायर मिल जाएंगे। इसमें प्रिमसी, पायलट स्पोर्ट, लैटिट्यूड स्पोर्ट और एलटीएक्स ट्रेल जैसी लोकप्रिय सीरीज शामिल हैं। टायर्स से जुड़े कामों के लिए यह एक बेहतरीन वन–स्टॉप जगह है। यहां आधुनिक व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ऑटोमोटिव एक्सेसरीज और रिपेयरिंग व मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों को बेहतरीन और सुविधाजनक सेवा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे ग्राहकों के लिए वाहन रखरखाव का अनुभव और भी आसान हो जाता है।

इस नई सुविधा का उद्घाटन मिशलिन इंडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर श्री. बेंजामिन कोएसनॉन द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाशक्ति ऑटो की पूरी टीम उपस्थित थी।

मिशलिन इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री. शांतनु देशपांडे ने कहा, "उत्तर भारत में मिशलिन के विस्तार की दृष्टि से जम्मू एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह शहर क्षेत्रीय व्यापार और पारगमन का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहां सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले

टायरों की मांग लगातार बढ़ रही है। हमारे इस नए 'मिशलिन टायर्स एंड सर्विस' स्टोर के माध्यम से ग्राहकों को उनके निकट ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होंगी। हाल ही में लॉन्च किए गए मेड इन इंडिया प्रिमसी 5'टायरों की तर्ज पर हम भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते रहेंगे।"

जम्मू के रास्ते देश के सबसे चुनौतीपूर्ण ड्रायविंग मार्गों में माने जाते हैं। पहाड़ों पर तीव्र चढ़ाई,तीखे मोड़ और बदलते मौसम के कारण यहां यात्रा के दौरान अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वाहन की पकड़, ब्रेकिंग स्टेबिलिटी के साथ–साथ टायर्स की मजबूती भी बहुत जरूरी होती है। उच्च गुणवत्ता वाले टायर्स के साथ उनका सही रखरखाव भी महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं टायर्स की वजह से यात्री सुरक्षित रहते हैं। इस क्षेत्र की सड़कों और ड्राइविंग की स्थितीयों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों को उपयुक्त टायर उपलब्ध कराने के लिए यह नया स्टोर स्थापित किया गया है। इस स्टोर में टायर्स के चयन के लिए विशेषज्ञों द्वारा सलाह भी दी जाती है।

महाशक्ती ऑटो को जम्मू के ऑटोमोटिव क्षेत्र में 30 वर्षों का दीर्घ अनुभव है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और तकनीकी दक्षता के लिए महाशक्ती ऑटो की ख्याति सर्वत्र प्रसिद्ध है। महाशक्ती ऑटो की जम्मू के स्थानीय बाजार में मजबूत पकड़ और मिशलिन की अंतरराष्ट्रीय टायर तकनीक इस साझेदारी के माध्यम से एक साथ आई हैं। इससे ग्राहकों को सुरक्षित, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

हवाई सफर में भूलकर भी न ले जाएं यह पावरबैंक

इंडिगो विमान में आग के बाद डीजीसीए का सख्त फैसला, जानें और कौन सी चीजों पर हैं बैन

नई दिल्ली। हवाई सफर के दौरान पावरबैंक ले जाना हमारे लिए आज के समय में कितना आम है यह सब जानते हैं और सिर्फ फ्लाइट में ही नहीं किसी भी सफर में पावरबैंक तो हमारा गो टू हो ही गया है। मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर पावरबैंक काम आता है, लेकिन अब एक खास मॉडल का पावरबैंक यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मोबिकिंस एमके–पीबी–04 पावरबैंक को भारत आने–जाने वाली और देश के भीतर चलने वाली सभी यात्री और कार्गो उड़ानों में ले जाने पर रोक लगा दी है। यह फैसला विमान में आग लगने की हालिया घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

दरअसल, 11 अक्टूबर को दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आग लगने के बाद विमान को हैदराबाद की ओर मोड़ना पड़ा था। इस घटना ने उड़ान के दौरान लिथियम–आयन बैटरी वाले उपकरणों से पैदा होने वाले खतरे को फिर सामने ला दिया। डीजीसीए ने एयरलाइंस और यात्रियों को इस खास मॉडल को विमान में किसी भी रूप में नहीं ले जाने की सलाह दी है।

डीजीसीए प्रमुख वीर विक्रम यादव के आदेश के मुताबिक, मोबिकिंस एमके–पीबी–04 मॉडल को विमान में ले जाना या कार्गो के रूप में भेजना प्रतिबंधित है। एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वेरू जांच के दौरान इस मॉडल की पहचान करें और इसे विमान में ले जाने से रोकें। यात्रियों को उचित माध्यमों से सुरक्षा संबंधी सूचना दें। विमान में इसकी ढुलाई रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

पावरबैंक के अलावा भी विमान में कई ऐसी चीजें ले जाने पर रोक है, जो आग, विस्फोट या यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि, कुछ चीजों पर पूरी तरह रोक है, जबकि कुछ को तय मात्रा और शर्तों के साथ ले जाने की अनुमति मिलती है।ज्वलनशील चीजेंरू पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पटाखे और विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है।

'बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के उगाई गई सब्जियों एवं फलों में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है': बाबा उमाकान्त जी महाराज

फल और सब्जी उगाने के लिए अगर गोबर और जली हुई नीम की पत्तियों की राख को काम में लिया जाए तो उस सब्जी व फल में मिठास रहती है

जम्मू। सीकर, राजस्थान परम् पूज्य परम् सन्त बाबा उमाकान्त जी महाराज ने सतसंग में कहा कि इस समय प्राकृतिक चीजें मिलती ही कहां हैं?जो चीजें आप बाजार से लाते हो वे खाद डाल करके, गंदा पानी डाल के तैयार की हुई रहती है। अगर किसी के पास इतनी जमीन और साधन सुविधा है तो आप घर में ही सब्जी वगैरह उगा लो तब आपको बगैर खाद की सब्जी और फल मिल जाएंगे।

इन सब चीजों में ज्यादा तत्व मिलते है। जो घर में उगाते हो, उसमें आप गोबर का खाद डाल दो, कीटनाशक दवा की जगह नीम की पत्ती को जला करके उसकी राख बना करके उसके ऊपर डाल दो, गोबर घोल करके डाल दो तो कीड़े नहीं

आते है, उस सब्जी में आप देखना कितनी मिठास रहती है।

वह बहुत तत्व देने वाली होती है। जो दाल आप घर में बनाते हो उसमें आप देखो कितनी मिठास रहती है जबकि बाजार वाले में तो उसको सुन्दर बनाने के लिए निकल लगा देते है, पॉलिश कर देते है। आप सबको प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है।

मोटे अनाज जिनको पहले कोई पूछता भी नहीं था, अब उसी का पैकेट बाजारों में कई गुना ज्यादा दाम में बिकता है

देखो! अब वही चीजें अब फिर से आने लग गई। राजस्थान वाले जो बाजरा खाते है, उन्हें पहले लोग कहते थे कि ये सीमेंट की रोटी खाते है लेकिन अब वही पैकेट में बंद हो होकर के आता है और बाजरे से दस गुना दाम देकर के लोग उसको खरीद करके लाते है।

मेडुवा, काकुन और समा को तो कोई पूछता भी नहीं था लेकिन अब उसी की कीमत हो गई, वही आज दुकानों पर पैकेट में बंद हो होकर के आ रहा है और कई गुना दे करके लोग उसको ला रहे है और खा रहे है। कहते है कि इसको खाने से पेट साफ होता है।

नवनियुक्त डीसी ने उधमपुर जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की कि समीक्षा

जम्मू। अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। उधमपुर के नवनियुक्त उपायुक्त अनंत द्विवेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वियन का आकलन करने के लिए एक परिचयात्मक–सह– समीक्षा बैठक बुलाई।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, पीओ पोषण सुभाष डोगरा, मुख्य योजना अधिकारी उत्तम सिंह, महाप्रबंधक डीआईसी किशोर सिंह कटोच, एसीआर डॉ. उमेश शान और अन्य वरिष्ठ जिला एवं क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे।

डीसी ने संबंधित विभागों के कामकाज पर अधिकारियों से विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी और सरकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों के कार्यान्वियन की स्थिति की समीक्षा की।

डीसी ने चल रहे विकास कार्यों की परियोजनावार, योजनावार और क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा की, जिसमें उधमपुर में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण, पीएमडीपी के तहत स्वीकृत मानतलाई में पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास, एनएचआईडीसीएल परियोजनाएं, जनजातीय विकास योजना का कार्यान्वियन और जिला

पूंजीगत व्यय बजट 2026–27 के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति शामिल है।

उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भौतिक प्रगति की भी समीक्षा की और स्वास्थ्य, वीबी–जी राम जी, ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, जेपीडीसीएल, पीएमएवाई –जी, पीएमएवाई– शहरी, जल जीवन मिशन, आईसीडीएस, जल शक्ति, पीएमजीएसवाई, मिशन युवा, जेके समाधान और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित प्रमुख क्षेत्रों और योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन किया।

डीसी ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को काम की गति तेज करने, पर्याप्त जनशक्ति और मशीनरी जुटाने और गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

जवाबदेही और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण पर जोर देते हुए, उन्होंने जनता की शिकायतों के समय पर और संतोषजनक निवारण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चल रहे कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करें, अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में जमीनी दौरे करें, बाधाओं की पहचान करें और विकास पहलों के प्रभावी कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए त्वरित सुधारात्मक उपाय करें।

डीसी ने सभी अधिकारियों से सरकारी कार्यालयों में जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाने और पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लक्षित कार्यान्वियन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचें।

उपायुक्त ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों के समाधान के लिए कार्रवाई उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने और लोगों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

सर्दियां प्रारंभ होते ही गुर्जर–बकरवाल समुदाय ने अपने मवेशियों के साथ मैदानी क्षेत्रों का किया रूख

उधमपुर, 14 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गुर्जर–बकरवाल समुदाय ने अपनी भेड़– बकरियों, मवेशियों आदि को लेकर मैदानी क्षेत्रों का रुख करना प्रारंभ कर दिया है।

डेरों के साथ चल रहे सदस्यों जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों में ज्यादा समय नहीं बचा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फवारी होना प्रारंभ हो गई, जिसको देखते हुए उन्हें मैदानी इलाकों का रूख करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि वह सर्दियों में मैदानी क्षेत्रा का रूख करते है जबकि गर्मियां आने पर वह पहाड़ी इलाकों की ओर रुख करते है इस दौरान उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें इसके लिए पहले अपने परिवार के कुछ सदस्यों को आगे भेजना पड़ता है ताकि वह उस जगह का चयन कर सकें, जहां उन्हें अगले छः माह तक रुकना होता है। वहां पर बाकी इंतजाम करने पड़ते है ताकि जो डेरे के साथ चल रहे सदस्य है उनको पहुंचने पर कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई कई दिन लग जाते है इस दौरान उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है।

गौर रहे कि हर 6 माह उपरांत जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही गुर्जर–बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के साथ मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों का रूख करते है।

Created by Universal Document Converter

मां कुष्मांडाः सृष्टि की सृजनकर्ता, दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक चेतना की अधिष्ठात्री

विश्वनाथ झा

"या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः" जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार तथा शून्यता व्याप्त थी, तब अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली आदिशक्ति के रूप में मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि उनकी मुस्कान से सृष्टि में ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का संचार हुआ। इसी कारण उन्हें सृजन और चेतना की प्रतीक माना जाता है। सनातन परंपरा में मां दुर्गा जगत की मूल शक्ति हैं। उनके स्वरूप संरक्षण, करुणा, साहस और धर्म की स्थापना का संदेश देते हैं। मां कूष्मांडा इस शक्ति के सृजनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका स्वरूप बताता है कि शक्ति का उद्देश्य केवल संकटों का सामना करना नहीं, बल्कि संभावनाओं को जन्म देना और जीवन को कल्याणकारी दिशा देना भी है।

निराशा से आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं मां कूष्मांडा

देवी की उपासना आस्था के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। जीवन में निराशा, भय और अनिश्चितता के क्षण आते हैं, लेकिन आशा की छोटी–सी किरण भी मन में नया उत्साह जगा सकती है। मां कूष्मांडा की दिव्य मुस्कान इसी आशावाद और आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी आराधना हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने, विवेक से निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सीख देती है। नवरात्र का यह अवसर आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और सकारात्मक संकल्प का संदेश देता है। मां कूष्मांडा की कृपा का स्मरण करते हुए हमें अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानना चाहिए और अपने कर्मों से परिवार, समाज तथा प्रकृति के कल्याण में योगदान देना चाहिए। यही उनकी उपासना का आध्यात्मिक संदेश है।

मां कूष्मांडा नाम का अर्थ और उसका आध्यात्मिक रहस्य

मां कूष्मांडा के नाम को समझने के लिए सृजन से जुड़ी पौराणिक मान्यता जानना आवश्यक है। धार्मिक परंपरा के अनुसार, सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार और शून्यता थी, तब आदिशक्ति ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृजन और जीवन की मूल ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। उनके नाम की प्रतीकात्मक व्याख्या में 'कु', 'उष्मा' और 'अंड' को क्रमशः लघुता, ऊर्जा अथवा ऊष्मा और ब्रह्मांडीय अंड से जोड़ा जाता है। इसे आध्यात्मिक व्याख्या समझना चाहिए। यह विचार भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की उस परंपरा को दर्शाता है, जिसमें समस्त सृष्टि के पीछे मूल चेतना और ऊर्जा की कल्पना की गई है। मां कूष्मांडा का स्वरूप विराट ब्रह्मांड को मातृ शक्ति के रूप में देखने की धार्मिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। उनकी महिमा सिखाती है कि बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे संकल्पों से आरंभ होते हैं। जिस प्रकार छोटा बीज विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है, उसी तरह सुविचार समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। संवेदनशील व्यवहार, सेवा और सद्कर्म किसी के जीवन में आशा जगा सकते हैं। देवी का संदेश है कि ऊर्जा और संकल्प को सही दिशा देकर व्यक्तिगत प्रयासों को व्यापक कल्याण का माध्यम बनाया जा सकता है।

पौराणिक कथाः जब देवी की मुस्कान से हुआ ब्रह्मांड का सृजन

मां कूष्मांडा की महिमा से जुड़ी पौराणिक मान्यता सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। धार्मिक आख्यानों के अनुसार, सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा और न ग्रह–नक्षत्रों का प्रकाश। ऐसी मान्यता है कि उस समय आदिशक्ति ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी सृजनात्मक ऊर्जा से प्रकाश और गति का संचार हुआ तथा जीवन की संभावनाएं विकसित हुईं। इसी कारण मां कूष्मांडा को सृष्टि की मूल ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप सृजन को केवल निर्माण नहीं, बल्कि जीवन, व्यवस्था और विकास की संभावनाओं के विस्तार के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। भारतीय धार्मिक चिंतन में यह कथा मातृशक्ति के माध्यम से सृष्टि की विराटता व्यक्त करती है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विवरण नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति है। इस कथा का मानवीय संदेश भी महत्वपूर्ण है। निराशा और अनिश्चितता के बीच नई शुरुआत का साहस परिवर्तन का पहला कदम बनता है। मां कूष्मांडा की दिव्य मुस्कान विश्वास जगाती है कि गहरे अंधकार में भी प्रकाश की संभावना बनी रहती है। सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।

मां कुष्मांडा का दिव्य स्वरूपः अष्टभुजाधारी देवी की महिमा

मां कूष्मांडा को तेजस्वी, सौम्य और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सामान्यतः अष्टभुजाधारी स्वरूप में दर्शाया जाता है, जो उनकी सृजनात्मक शक्ति, सामर्थ्य और संरक्षण का प्रतीक है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतकलश, चक्र, गदा और जपमाला जैसी वस्तुएं तथा आयुध दिखाई देते हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं और चित्रणों में उनके स्वरूप में कुछ अंतर भी मिलते हैं। देवी के हाथों में मौजूद प्रत्येक प्रतीक विशेष आध्यात्मिक संदेश देता है। कमल पवित्रता और आत्मिक जागरण का प्रतीक है। कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता बनाए रखने वाला कमल कठिन परिस्थितियों में भी मूल्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। चक्र धर्म, व्यवस्था और समय की गति का बोध कराता है, जबकि गदा शक्ति और अन्याय के प्रतिरोध का प्रतीक है। धनुष–बाण लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का संदेश देते हैं। कमंडल तप, संयम और साधना से जुड़ा है, जपमाला भक्ति तथा आत्मचिंतन की प्रतीक है और अमृतकलश आरोग्य, कल्याण एवं समृद्धि की कामना को दर्शाता है। मां कूष्मांडा का अष्टभुजाधारी स्वरूप सिखाता है कि जीवन को संतुलित और सार्थक

बनाने के लिए केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं है। ज्ञान, धैर्य, करुणा, आत्मसंयम और विवेक का समन्वय भी आवश्यक है। देवी के प्रतीक इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं।

सिंहवाहिनी मां कुष्मांडाः साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता का संदेश

मां कुष्मांडा को सिंहवाहिनी के रूप में भी पूजा जाता है। सिंह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता का प्रतीक है। देवी का सिंह पर विराजमान होना सिखाता है कि वास्तविक शक्ति विवेक और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करने में निहित है। सिंह नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति का भी प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने तथा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में सामाजिक दबाव, असफलता का भय और भविष्य की अनिश्चितता अक्सर मनुष्य को उसके उद्देश्य से विचलित कर देते हैं। ऐसे समय में मां कुष्मांडा की आराधना आत्मविश्वास बनाए रखने और उचित मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। उनका स्वरूप बताता है कि साहस केवल संघर्ष करने में नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच अंतर पहचानकर न्याय के पक्ष में खड़े होने में भी है। देवी का सिंहवाहिनी रूप शक्ति और करुणा के समन्वय का संदेश देता है। शक्ति का उपयोग दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा, अन्याय का प्रतिरोध और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए होना चाहिए। यही भावना मनुष्य को साहसी, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ बनाती है।

सूर्य के तेज और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा देवी का स्वरूप

मां कुष्मांडा को तेजस्विता और जीवनदायी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र की धार्मिक परंपरा में उनका संबंध सूर्य के प्रकाश और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा जाता है। सूर्य की रोशनी और ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसी महत्ता के कारण भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवत्व प्रदान किया गया है। मां कुष्मांडा का तेजस्वी स्वरूप इसी जीवनदायी शक्ति का आध्यात्मिक स्मरण कराता है। सूर्य प्रतिदिन उदित होकर संसार को प्रकाश देता है। बादल कुछ समय के लिए उसकी किरणों को ढक सकते हैं, लेकिन उसका प्रकाश समाप्त नहीं होता। यह प्राकृतिक अनुभव मनुष्य को धैर्य, निरंतरता और कर्मशीलता की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार, मां कुष्मांडा की आराधना व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानने और उनका सदुपयोग करने का संदेश देती है। प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट गुण होते हैं, जिन्हें परिश्रम, उचित मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण से समाजोपयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रकार, देवी का तेजस्वी स्वरूप जीवन में आशा, आत्मविश्वास और सृजनशीलता बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

अनाहत चक्र और हृदय की शुद्धताः प्रेम, करुणा और संतुलन

कुछ योग और साधना परंपराओं में मां कुष्मांडा की आराधना को अनाहत चक्र से जोड़ा जाता है। योग परंपरा में अनाहत चक्र का संबंध हृदय क्षेत्र, प्रेम, करुणा, सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन से माना जाता है। इस दृष्टि से देवी की उपासना मनुष्य को संवेदनशीलता, उदारता और मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। हृदय की शुद्धता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख–दुख को समझने और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने में भी प्रकट होती है। क्षमा, सहयोग और परस्पर सम्मान जैसे गुण परिवार तथा समाज में सौहार्द बढ़ाते हैं। आज की व्यस्त जीवनशैली में तनाव और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझने से चूक जाते हैं। ऐसे में ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन अपने व्यवहार को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। मां कुष्मांडा की आराधना का यह आध्यात्मिक संदेश है कि आंतरिक शक्ति के साथ करुणा, आत्मविश्वास के साथ विनम्रता और दृढ़ता के साथ संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही गुण व्यक्तित्व को परिपक्व और जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं।

नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का महत्व

शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा और विधि–विधान से की जाती है। भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूजा स्थल पर देवी का ध्यान करते हुए पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसके बाद मंत्र–जप और आरती की जाती है। पूजन–पद्धति में क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार अंतर हो सकता है। श्रद्धालु देवी से सुख–समृद्धि, आरोग्य, मानसिक शांति, साहस और परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। अनेक भक्त उपवास भी रखते हैं, जिसमें खान–पान के संयम के साथ विचारों की शुद्धता को महत्व दिया जाता है। देवी की आराधना का उद्देश्य केवल मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि सद्गुणों का विकास भी है। नवरात्र आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है। इस दौरान व्यक्ति क्रोध, अहंकार और कटुता त्यागने, कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने तथा जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प ले सकता है। यही साधना को सार्थक बनाता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है।

मां कुष्मांडा का प्रिय भोग और प्रसाद की परंपरा

नवरात्र की प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कुष्मांडा को मालपुआ अर्पित करने की परंपरा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में फल, मिठाई, हलवा और अन्य सात्विक व्यंजन भी भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। भोग की सामग्री स्थानीय रीति–रिवाजों और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। भारतीय संस्कृति में देवी को भोग अर्पित करना श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह परंपरा मनुष्य को जीवन में प्राप्त सुख–सुविधाओं के प्रति आभार व्यक्त करने और विनम्र बने रहने की प्रेरणा देती है। प्रसाद ग्रहण करने और बांटने से आपसी सहयोग तथा सहभागिता की भावना मजबूत होती है। धार्मिक आयोजनों में प्रसाद वितरण लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। जब परिवार और समुदाय के लोग मिलकर पूजा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं, तो उनके बीच आत्मीयता और सद्भाव बढ़ता है। इस प्रकार, भोग और प्रसाद की परंपरा का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता, साझेदारी और परस्पर सौहार्द को भी प्रोत्साहित करती है।

मां कुष्मांडा के मंत्रः भक्ति, एकाग्रता और आत्मचिंतन का माध्यम

देवी की उपासना में मंत्र–जप का विशेष महत्व है। मंत्रों का उच्चारण मन को एकाग्र करने और आराध्य के स्वरूप का स्मरण करने में सहायक होता है। मां कुष्मांडा की स्तुति के लिए विभिन्न धार्मिक परंपराओं में मंत्रों का पाठ किया जाता है। मां कुष्मांडा का ध्यान मंत्र "सुरासम्पूर्णकलश रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे॥" इस मंत्र में देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनसे शुभता और कल्याण की कामना की जाती है। देवी की सर्वव्यापक शक्ति का मंत्र "या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥" इसका भाव है कि समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान देवी को बार–बार नमन है। यह मंत्र प्रत्येक जीव में निहित जीवन–शक्ति के प्रति सम्मान की प्रेरणा देता है। मां कुष्मांडा का बीज मंत्र "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डायै नमः॥" इस मंत्र का जप श्रद्धालु भक्ति और एकाग्रता के साथ करते हैं। विभिन्न साधना–पद्धतियों में मंत्र–जप की विधि अलग हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मंत्र–साधना मन को स्थिर करने, आत्मचिंतन और विचारों को व्यवस्थित करने का माध्यम है। हालांकि, इसे अपने कर्तव्यों और व्यावहारिक प्रयासों का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

मां कुष्मांडा और नारी शक्तिः सृजन तथा संरक्षण का अद्भुत संगम

मां कुष्मांडा का स्वरूप नारी शक्ति की व्यापकता और सृजनात्मक सामर्थ्य का प्रतीक है। उनकी उपासना जीवन के सृजन, संरक्षण और संवर्धन करने वाली शक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को प्राचीन काल से सम्मान दिया जाता रहा है। मातृत्व केवल संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि उसे संस्कार, शिक्षा, सुरक्षा और संवेदनशीलता प्रदान करना भी है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, साहित्य, कला, कृषि और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मां कुष्मांडा की आराधना हमें प्रेरित करती है कि नारी का सम्मान केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित न रहे, बल्कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समान अवसर और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी मिले। महिलाओं की गरिमा और अधिकारों का संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। देवी का सृजनात्मक स्वरूप यह संदेश देता है कि परिवार और समाज का वास्तविक विकास सहयोग, संवेदना और समान भागीदारी से संभव है। जब महिलाओं को अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर मिलते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इस प्रकार, नारी शक्ति की आराधना सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन की प्रेरणा बन सकती है।

प्रकृति संरक्षण और सृजन की शक्तिः पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी

मां कुष्मांडा को सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्मरण करना प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को समझने की प्रेरणा देता है। जल, वायु, मिट्टी, वनस्पतियां और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के आधार हैं। आज प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग और प्लास्टिक के सीमित इस्तेमाल जैसे कदम पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। मां कुष्मांडा की उपासना हमें सृजन और संरक्षण के महत्व का बोध कराती है। प्रकृति के प्रति सच्ची कृतज्ञता उसके संसाधनों का सम्मान करने और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने में निहित है।

मां कुष्मांडा की महिमा और आधुनिक जीवन की चुनौतियां

आज का जीवन तेज गति, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताओं से भरा है। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच अनेक लोग मानसिक दबाव का अनुभव करते हैं। ऐसे समय में आध्यात्मिक परंपराएं व्यक्ति को आत्मचिंतन, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान कर सकती हैं। मां कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान हमें सिखाती है कि आशावाद का अर्थ कठिनाइयों को नकारना नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए मानसिक शक्ति जुटाना है। समस्या का समाधान खोजने के लिए धैर्य, विवेक और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। निराशा में डूबे रहने के बजाय परिस्थितियों को समझना और उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकता है। देवी का तेजस्वी स्वरूप आत्मविश्वास और कर्मशीलता का संदेश देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। उसके लिए योजना, अनुशासन, ज्ञान और मेहनत भी जरूरी हैं। इसी तरह असफलता को अंतिम परिणाम मानने के बजाय उससे सीख लेकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष दूसरों के प्रति संवेदनशील होना भी है। परिवार के सदस्यों की बात सुनना, जरूरतमंदों की सहायता करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और अपने कार्यों में ईमानदारी बरतना ऐसे गुण हैं, जो जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। मां कुष्मांडा की आराधना इन मूल्यों को अपनाने का अवसर प्रदान करती है।

सेवा, सद्भाव और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पूजा और सेवा को परस्पर पूरक माना गया है। देवी की आराधना तभी व्यापक अर्थ ग्रहण करती है, जब वह समाज के प्रति संवेदनशीलता और कर्तव्यबोध भी जगाए। गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग देना, बीमारों की सहायता करना और संकटग्रस्त परिवारों के साथ खड़े होना सेवा के ऐसे रूप हैं, जो सामाजिक विश्वास और आत्मीयता को मजबूत करते हैं। सेवा के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। बुजुर्गों की सहायता करना, किसी की बात ध्यान से सुनना और जरूरतमंद को उचित मार्गदर्शन देना भी महत्वपूर्ण योगदान है। मां कुष्मांडा का सृजनात्मक स्वरूप हमें दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। नवरात्र की भक्ति को सामाजिक सहयोग, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और परोपकार से जोड़कर उसकी सार्थकता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार आस्था दैनिक व्यवहार में करुणा, सहयोग और मानवीय मूल्यों के रूप में अभिव्यक्त होती है।

सृजन, प्रकाश और आशा की अधिष्ठात्री मां कुष्मांडा

मां कुष्मांडा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सृजन, ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मक चेतना की प्रतीक हैं। उनकी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पौराणिक मान्यता जीवन में नई संभावनाओं और आशा का संदेश देती है। उनका अष्टभुजाधारी स्वरूप सामर्थ्य तथा सिंहवाहिनी रूप साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता का प्रतीक है। नवरात्र के चौथे दिन उनकी आराधना आत्मचिंतन और सद्कर्मों के संकल्प का अवसर प्रदान करती है। मां कुष्मांडा की महिमा से प्रेरणा लेकर मनुष्य निराशा के स्थान पर आशा, कटुता के स्थान पर करुणा और निष्क्रियता के स्थान पर कर्मशीलता को अपना सकता है। नारी सम्मान, प्रकृति संरक्षण, सामाजिक सेवा और मानवीय सद्भाव उनके सृजनात्मक स्वरूप के संदेश को जीवन से जोड़ते हैं। देवी का आध्यात्मिक संदेश है कि प्रकाश की शुरुआत भीतर से होती है। सकारात्मक विचारों, कर्तव्यनिष्ठा और परोपकार से व्यक्ति समाज में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। उनकी आराधना हमें सिखाती है कि विवेक, धैर्य और साहस से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। मां कुष्मांडा की कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और सद्बुद्धि का संचार हो। उनके चरणों में कोटि–कोटि नमन।

Created by Universal Document Converter

बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों ने पंजाबी भाषा के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से की मुलाकात

आरएस पुरा। बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल से नई दिल्ली में उनके साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने संबंधी उन्हें एक ज्ञापन सोपा। इस मौके पर बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान सरदार हरप्रीत सिंह, उपाध्यक्ष बलमीत सिंह, चेयरमैन डॉ. सतवंत सिंह रिशम, महासचिव जगजोत सिंह रैना तथा ट्रस्ट के एडवाइजर मनजीत सिंह सहित ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी भी प्रतिनिधिमंडल में

मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधान हरप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल को जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से पिछले लंबे समय से प्रयास भी किया जा रहे है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में लागू होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा बोलने तथा पढ़ने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता के साथ रखें ताकि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा जल्द से जल्द आधिकारिक भाषा के रूप में लागू हो सके। इस मौके पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी मांग को प्रमुखता के साथ लिया जाएगा और केंद्र सरकार तक रखा जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द पंजाबी भाषा लागू हो सके। इस मौके पर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी।

कृषि ट्रैक्टर के पंजीकरण के लिए अधिक शुल्क सुनने के विरोध में किया गया प्रदर्शन

आरएस पुरा। जम्मू–कश्मीर में कृषि ट्रैक्टर के पंजीकरण के लिए अन्य

राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में अधिक शुल्क होने के खिलाफ बुधवार को किसानों ने आरएस पुरा के टाली मोड चौक में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ–साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग करते हुए कहा कि ट्रैक्टर के पंजीकरण पर लगने वाली फीस में कटौती की जानी चाहिए जिसके लिए जम्मू संभाग के किस पिछले लंबे समय से मांग करते आ रहे है। पूर्व सरपंच एवं किसान नेता सुखदेव सिंह काला की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

इस मौके पर पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह काला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के मुकाबले कृषि ट्रैक्टर पंजीकरण की फीस काफी ज्यादा है जिसका किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किस किसी तरह से ट्रैक्टर तो खरीद लेता है लेकिन उसके पंजीकरण पर काफी खर्चा आ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जब आरएस पुरा दौरे पर पहुंचे थे तो किसानों ने उनके समक्ष भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखा था लेकिन अभी तक किसान वर्ग की इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में ट्रैक्टर के पंजीकरण की फीस जम्मू कश्मीर के मुकाबले काफी कम है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द किसानों को राहत नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी।

प्रवीण सिंह सर्वसम्मति से चिब बिरादरी परगवाल के अध्यक्ष निर्वाचित

परगवाल। चिब बिरादरी परगवाल ने प्रवीण सिंह चिब को सर्वसम्मति से बिरादरी का अध्यक्ष निर्वाचित किया। अध्यक्ष चुने जाने पर प्रवीण सिंह ने बिरादरी के सभी सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रमेश सिंह ने प्रवीण सिंह को माता की चुनरी पहनाकर सम्मानित किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने इस सम्मान के लिए उनका विशेष धन्यवाद किया। प्रवीण सिंह ने कहा कि बिरादरी के सदस्यों ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह बिरादरी की एकता, सम्मान और हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद उनके लिए केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बिरादरी की सेवा करने का सौभाग्य है। वह सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे और बिरादरी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वह सदस्यों की उम्मीदों पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

रंघवाल में नवरात्रि दंगल का दिखा जोश, नामी पहलवानों ने आजमाया दमखम; अंजू बाबा रहीं आकर्षण का केंद्र

घगवाल (निखिल पंगोत्रा)। नवरात्रि पर्व के अवसर पर उपजिला घगवाल के रंघवाल गांव में आयोजित विशाल दंगल में कुश्ती के रोमांचक मुकाबलों ने माहौल को पूरी तरह जोश से भर दिया। दंगल में आसपास के गांवों के अलावा दूर–दराज के क्षेत्रों से भी पहलवान पहुंचे और अखाड़े में अपने हुनर व दमखम का प्रदर्शन किया।

अखाड़े में पहलवानों के बीच हुए मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जैसे–जैसे मुकाबले आगे बढ़े, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया। शानदार दांव–पेच देखने के बाद दर्शकों ने तालियों और उत्साहवर्धन के साथ पहलवानों का हौसला बढ़ाया। अंजू बाबा की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय दंगल में किन्नर समाज की अंजू बाबा अपनी टीम के साथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं। उनके पहुंचने पर आयोजकों और स्थानीय लोगों की ओर से स्वागत किया गया। अंजू बाबा ने अखाड़े में पहुंचे पहलवानों का उत्साह बढ़ाया और आयोजन में शामिल होने

पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले ऐसे पारंपरिक दंगल खेल भावना के साथ–साथ आपसी भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। अंजू बाबा की मौजूदगी दंगल में लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही। नवरात्रि पर्व में दिखी ग्रामीण खेल संस्कृति की झलक रंघवाल का यह दंगल धार्मिक उत्सव के बीच पारंपरिक खेल संस्कृति का भी परिचय देता नजर आया। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और स्थानीय ग्रामीण अखाड़े के आसपास मौजूद रहे। कुश्ती के मुकाबलों के दौरान पूरा क्षेत्र दर्शकों की तालियों और उत्साह से गूंजता रहा।

आयोजकों की ओर से दंगल को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं। स्थानीय लोगों ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के पारंपरिक खेल आयोजनों से नई पीढ़ी को कुश्ती और अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है।

इस मौके पर जनक राज, बलराम सिंह पप्पी, सोहन सिंह लंबरदार, राजू, राजू रंघवाल, मुख्तार सिंह, रमणीक सिंह, सोनू लंबरदार, जनक भारद्वाज, दीप सिंह, जय राम शर्मा, केवल सिंह, अवतार सिंह, रूप सिंह रंघवाल, दीपक सिंह, काका सिंह, थूथन सिंह, सुरेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, मितू फौजी और रामपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नवरात्रि के मौके पर आयोजित इस दंगल ने रंघवाल में पारंपरिक खेल, उत्साह और ग्रामीण भाईचारे का माहौल कायम कर दिया।

सैनिक स्कूल नगरोटा में वार्शिक इंटर-हाउस एथलेटिक मीट-2026 की शुरूआत

जम्मू। सैनिक स्कूल नगरोटा की सालाना इंटर–हाउस एथलेटिक मीट–2026 की शुरूआत मेजर सोमनाथ शर्मा, पीवीसी, स्टेडियम में बड़े उत्साह और खेल के जोश के साथ हुई। स्कूल के प्रिंसिपल कैप्टन (आईएन) शिबू देवासिया मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह की शुरूआत हिस्सा लेने वाली टीमों के मार्च पास्ट से हुई जिसमें उन्होंने अपना अनुशासन, तालमेल और टीम भावना दिखाई। इसके बाद स्पोर्ट्स कैप्टन कैडेट आदर्श तिवारी ने एथलेटिक मशाल जलाई जो खेल भावना, लगन और बेहतरीन प्रदर्शन का प्रतीक है।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कैप्टन (आईएन) शिबू देवासिया ने कैडेटों के सर्वांगीण विकास में खेलों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने से शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, नेतृत्व

क्षमता, अनुशासन और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने सभी एथलीटों से कहा कि वे पूरे संकल्प और सच्ची खेल भावना के साथ मुकाबला करते हुए अनुशासन और आपसी भाईचारे के ऊंचे मानकों को बनाए रखें। पहले दिन सीनियर और जूनियर लड़कों और लड़कियों की कैटेगरी में कई ट्रैक, रोड–रन और फील्ड इवेंट्स हुए। इन प्रतियोगिताओं में 400 मीटर बाधा दौड़, 200 मीटर और 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर दौड़, 4 . 100 मीटर और 4 . 400 मीटर रिले रेस, शाट पुट, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, ट्रिपल जंप और ऊंची कूद शामिल थीं।

सभी इवेंट्स में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला जिसमें कैडेटों ने शानदार एथलेटिक क्षमता, सहनशक्ति, संकल्प और टीम भावना का प्रदर्शन किया। पहले दिन के कार्यक्रमों ने इस मल्टी–इवेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए एक जोशीला माहौल बनाया और रक्षा बलों और देश के लिए शारीरिक रूप से फिट, अनुशासित और मजबूत भविष्य के लीडर तैयार करने के प्रति सैनिक स्कूल नगरोटा की प्रतिबद्धता को फिर से साबित किया।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: 1408, G H Skara, Near Ladakh Public School, Leh-Ladakh, Ladakh - 194101, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter